Samyak
An Institute For Civil Services

द्विमासिक
समसामयिकी घटनाचक्र

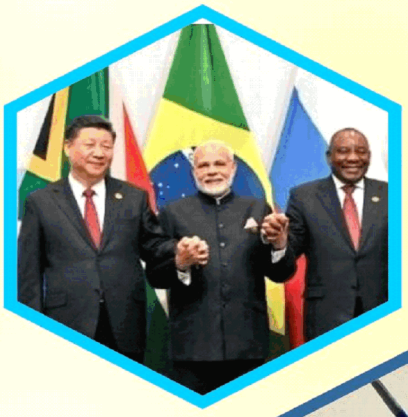

नवम्बर - दिसम्बर, 2019

करेंट अफेयर्स

अंतरराष्ट्रीय | राष्ट्रीय | राजस्थान | राजस्थान सुजस सार

रक्षा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | पुरस्कार | खेलकूद | चर्चित व्यक्ति/स्थान

सभी प्रतियोगी परिक्षाओं हेतु उपयोगी

आयुष्मान भारत

Near Riddhi-Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
✆ 9875170111, 9414988860

1 अन्तरराष्ट्रीय घटनाक्रम

■ भारत-जर्मनी के बीच 17 समझौतों पर हस्ताक्षर

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 31 अक्टूबर, 2019 को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आईं। मर्केल ने यहां 1 नवम्बर को आयोजित '5वें द्विवार्षिक भारत-जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श' कार्यक्रम की पीएम मोदी के साथ सह अध्यक्षता की। उन्होंने भारत में पर्यावरण अनुकूल आवागमन के क्षेत्र में आगामी पांच साल में एक अरब यूरो के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के बीच वार्ता के बाद आयुर्वेद व योग, कृषि बाजार विकास, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान, 108 उपनिषदों के जर्मन भाषा में अनुवाद सहित 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

■ पीएम मोदी की थाईलैंड यात्रा

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2-4 नवम्बर, 2019 को थाईलैंड की यात्रा पर रहे। यहां मेजबान प्रधानंमत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तथा आरसीईपी वार्ता में हिस्सा लिया।

भारत-आसियान शिखर सम्मेलनः- भारत के पीएम मोदी ने 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के एक भाग के तौर पर 3 नवम्बर को बैंकॉक में आयोजित 16वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता पीएम मोदी ने थाईलैंड के पीएम के साथ की।

आसियानः-आसियान (Association of South-East Asian Nations) की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को हुई थी। इसके 10 सदस्य देश हैं-इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, ब्रूनेई, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनः- 4 नवम्बर को पीएम मोदी ने 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में सम्बद्ध देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और अन्तरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार किया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के देशों का मंच है। यह इस क्षेत्र के देशों के बीच आपसी विश्वास निर्माण का कार्य करता है।

आरसीईपी की बैठकः- 4 नवम्बर को आयोजित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) की तीसरी बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए। भारत ने दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के 16 देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था के लिए प्रस्तावित 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी का तर्क था कि जब तक भारत को होने वाले असमान व्यापार घाटे और भारतीय व्यवसाय व उत्पादों के समान अधिकार नहीं मिलेंगे, भारत इस समझौते में शामिल नहीं होगा। आरसीईपी में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। आरसीईपी के समझौते के तहत सदस्य देशों को टेक्स घटाने होते हैं तथा व्यापार के लिए अनुकूलित वातावरण बनाना होता है।

स्वास्दी मोदीः- भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक के निमिबुत्र स्टेडियम में 'स्वास्दी पीएम मोदी' कार्यक्रम में 2 नवम्बर, 2019 को भारतीय समुदाय को सम्बोधित किया। यह कार्यक्रम अमेरिका के 'हाउडी मोदी' की तर्ज पर आयोजित किया गया। 'स्वास्दी' शब्द का प्रयोग थाई लोगों द्वारा बधाई और अलविदा कहने के लिए किया जाता है।

■ भारत-उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग समझौता

शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 18वीं बैठक नवम्बर, 2019 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई। बैठक में भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के विशेष दूत के रूप में शामिल हुए। इस बैठक से इतर भारत-उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों की 2 नवम्बर को हुई वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सम्बन्धों में सहयोग सम्बन्धी 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें सैन्य दवाओं के क्षेत्र में सहयोग, उच्च सैन्य शिक्षा संस्थानों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को लेकर दो संस्थानों के बीच किए गए एमओयू शामिल हैं।

■ पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका

अमेरिका द्वारा पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की औपचारिक सूचना 4 नवम्बर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र को दी

गई है। अमेरिका इस समझौते से अलग होने की घोषणा जून, 2017 में ही कर चुका था। अब इसकी सूचना यूएन को दिए जाने के बाद अमेरिका 4 नवम्बर, 2020 से इस समझौते से अलग हो जाएगा।

■ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 13-14 नवम्बर, 2019 को ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की विषय वस्तु थी 'एक नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास (Economic Growth for an Innoivative Future)।

इन बिन्दुओं पर हुई चर्चा:- प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को मजबूत करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग को बढ़ावा, विशेष रूप से संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई पर सहयोग, एनडीबी तथा ब्रिक्स। ब्रिक्स व्यापार परिषद ने अगले शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच 500 अरब डॉलर के परस्पर व्यापार का लक्ष्य हासिल करने की रूपरेखा तय की।

पीएम मोदी हुए शामिल:- भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके इतर पीएम मोदी ने रूस, चीन व ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ताएं कीं।

पुतिन से मुलाकात:- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की गई। पुतिन ने मोदी को वर्ष 2020 के विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया।

शी जिनपिंग से मुलाकात:- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के पीएम मोदी को मुलाकात के दौरान वर्ष 2020 में भारत-चीन के बीच होने वाले तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए चीन आने का न्योता दिया।

जायर मेसियस से मुलाकात:- ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मेसियस बोलसोनारो से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ब्राजील से कृषि उपकरण, पशुपालन, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और जैव ईंधन सहित कई क्षेत्रों में संभावित निवेश की रूपरेखा तैयार की गई। पीएम मोदी ने जायर को वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।

■ RCEP में शामिल नहीं होगा भारत

भारत सरकार ने 16 सदस्य देशों वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) समूह में शामिल न होने का निर्णय लिया है।

RCEP :- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या RCEP एक मुक्त व्यापार समझौता है, जो कि 16 देशों के मध्य किया जा रहा था। भारत के इसमें शामिल नहीं होने के निर्णय के पश्चात् अब इसमें 15 देश शेष हैं। इसमें 10 आसियान देश तथा उनके FTA भागीदार- भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार बनाना एवं सभी 16 देशों में फैले हुए बाजार का एकीकरण करना है। इसकी औपचारिक शुरुआत नवम्बर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी।

क्या है समस्या :- भारत के अतिरिक्त RCEP में भाग लेने वाले अन्य सभी 15 सदस्यों ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है। इस समझौते के वर्ष 2020 तक संपन्न होने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत का तर्क है कि RCEP अपने मूल उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता एवं इसके परिणाम न तो उचित हैं और न ही संतुलित।

■ बोलीविया में राजनीतिक संकट

मध्य-दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में अक्टूबर, 2019 में हुए चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बाद वहां की जनता के साथ-साथ सेना के बढ़ते दबाव में 10 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रपति इवो मोरालेस तथा उप राष्ट्रपति गार्सिया लिनेरा ने त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रपति इवो मोरालेस को मैक्सिको में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। इसके बाद यहां मोरालेस समथकों व प्रतिद्वंद्वियों में हुई हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई।

इस बीच विपक्ष की विधायक जीनिन अनीज ने स्वयं को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उन्होंने 25 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रपति के अधिकतम दो कार्यकाल का कानून पारित कर दिया। साथ ही नए आम चुनाव के लिए तारीख तय करने हेतु बोर्ड का गठन किया गया।

■ कॉप-25

जलवायु परिवर्तन पर 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' (कॉप) के 25वें सत्र का आयोजन 2-13 दिसम्बर, 2019 को स्पेन के मैड्रिड में किया गया। यह सम्मेलन चिली सरकार की अध्यक्षता में स्पेन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका आयोजन चिली में होना था लेकिन वहां अशांति के चलते इसका आयोजन नहीं किया गया था।

उद्देश्य:- इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2020 के बाद की अवधि में पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट मार्ग तैयार करना था।

उपलब्धि:- क्षमता निर्माण, लिंग आधारित कार्यक्रम व प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर कुछ समझौते हुए, किन्तु जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और उनसे निपटने के उपायों के लिए धन की व्यवस्था करना जैसे मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई।

पेरिस जलवायु समझौता:- इस ऐतिहासिक समझौते को वर्ष 2015 में 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क' (UNFCCC) की 21वीं बैठक में अपनाया गया, जिसे COP-21 के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को वर्ज़ 2020 से लागू किया जाना है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी देशों को वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है (दूसरे शब्दों में कहें तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है) और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए सक्रिय प्रयास करना है।

■ ब्रिटेन चुनाव : बोरिस जॉनसन की जीत

ब्रिटेन में 12 दिसम्बर, 2019 को हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत हासिल की। कंजर्वेटिव पार्टी को हाउस ऑफ कामन्स की 650 सीटों में से 365 सीटें प्राप्त हुईं। जबकि जेरेमी कार्बिन के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी 'लेबर पार्टी' को 203 सीटों पर जीत हासिल हुई। इन चुनावों में भारतीय मूल के 14 सांसद चुने गए हैं।

ब्रेक्जिट समझौते को मंजूरी:- चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए बिल पेश किया, जो निचले सदन ने 20 दिसम्बर, 2019 को पारित कर दिया।

■ भारत-अमेरिका की टू-प्लस-टू वार्ता

भारत और अमेरिका के बीच दूसरी टू-प्लस-टू मंत्री स्तरीय वार्ता 18 दिसम्बर, 2019 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में सम्पन्न हुई। वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस.जयशंकर व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया, वहीं मेजबान देश की ओर से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर शामिल हुए।

इन मुद्दों पर सहमति:- 1. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, रक्षा व्यापार बढ़ाने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए समान समझ वाले देशों के साथ समन्वय और आतंकवाद विरोधी संघर्ष पर सहमति बनी। 2. भारत व अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच नवम्बर, 2019 में आयोजित 'टाइगर ट्राइंफ' हर साल आयोजित होगा।, 3. चाबहार परियोजना पर प्रतिबंधों से भारत को मामूली छूट प्रदान की जाएगी।, 4. 'औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध' को अंतिम रूप दिया गया। यह रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग, महत्वपूर्ण सूचनाएं और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित हस्तांतरण की अनुमति देता है।

■ स्वीडन के राजा की भारत यात्रा

स्वीडन के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ तथा रानी सिल्विया हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे। इस मौके पर दोनों देशों के मध्य ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा समुद्री शुल्क के संबंध में समझौते हुए। साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भविष्य में गतिशीलता तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के विषय पर सहयोग देने की बात कही गई। एशिया में चीन तथा जापान के बाद भारत, स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

■ टाइफून कम्मुरी

'कम्मुरी' टाइफून दिसम्बर, 2019 में फिलीपींस के तट से टकराया। कम्मुरी, फिलीपींस में आने वाला इस वर्ष का 20वां टाइफून है।

टाइफून :- ऊष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं। अधिकांश टाइफून जून से नवम्बर के बीच आते हैं एवं दिसम्बर से मई के बीच भी सीमित टाइफून आते हैं तथा ये जापान, फिलीपींस और चीन को प्रभावित करते हैं।

■ फानफोन टाइफून

फानफोन टाइफून 25 दिसम्बर, 2019 को तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ फिलीपींस के तट से टकराया। कम्मुरी के बाद फिलीपींस के तट से टकराने वाला साल का 21वां दूसरा टाइफून है। प्रशांत महासागर में स्थित फिलीपींस ऐसा पहला बड़ा भू-क्षेत्र है जो प्रशांत महासागरीय चक्रवात बेल्ट से उठने वाले चक्रवातों का सामना करता है।

■ जी-20 का अगला मेजबान सऊदी अरब

हाल ही में सऊदी अरब G-20 की अध्यक्षता करने वाला अरब जगत का पहला देश बन गया है। यह 21-22 नवम्बर, 2020 को अपनी राजधानी रियाद में वैश्विक शिखर सम्मेलन में विश्व के बड़े नेताओं की मेजबानी करेगा।

G-20 :- G-20 की स्थापना 1999 में 7 देशों-अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी। G-20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। G-20 विश्व के आर्थिक उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत, वैश्विक जनसंख्या का दो-तिहाई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व करता है। G-20 का पहला शिखर सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 को वाशिंगटन डी.सी (संयुक्त राज्य अमेरिका) में हुआ था। वर्ष 2022 में भारत 17वें जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

■ वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक

उत्तरी स्पेन के बिलबाओ में पहली बार 'प्रॉस्पेरिटी एंड इन्क्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड्स' (Prosperity and Inclusion City Seal and Awards- PICSA) सूचकांक नवम्बर, 2019 में जारी किया गया है। सूचकांक में वैश्विक आर्थिक और सामाजिक समावेश के मामले में विश्व के शीर्ष 113 शहरों को शामिल किया गया है। सूची में सबसे निचले पायदान पर मिस्र की राजधानी काहिरा (113) है।

भारत के तीन शहरों को स्थान:-

स्थान	शहर
83	बेंगलूरु
101	दिल्ली
107	मुंबई

सूची में शामिल शीर्ष तीन शहर :-

स्थान	शहर
1	ज्यूरिख
2	वियना
3	कोपेनहेगन

■ म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर पुनडुब्बी

भारत ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी म्यांमार को देने का फैसला किया है और उसके नाविकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रूस निर्मित 'सिंधुवीर' 31 साल पुरानी है, लेकिन नई तकनीक से लैस है और इसकी उपयोगिता बनी हुई है।

■ भारत-बांग्लादेश तटीय नौपरिवहन समझौता

केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय नौपरिवहन समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश के मोंगला तथा चटगाँव बंदरगाह को 'पोर्ट्स ऑफ कॉल' (Ports of Call) घोषित किया गया है।

पोर्ट्स ऑफ कॉल :- पोर्ट्स ऑफ कॉल का आशय ऐसे बंदरगाह से है जिसका प्रयोग मालवाहक या यात्री (क्रूज) जहाज द्वारा सामान और यात्रियों को उतारने तथा चढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे बंदरगाहों का प्रयोग जलपोतों द्वारा ईंधन की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है।

■ फेनी नदी विवाद

यह नदी भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। इसका उद्गम दक्षिणी त्रिपुरा जिले में है। यह नदी त्रिपुरा के सबरूम शहर से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के जल के बंटवारे का विवाद काफी समय से लंबित है। त्रिपुरा के जल संसाधन विभाग के अनुसार, बांग्लादेश द्वारा आपत्ति के बाद फेनी नदी से जुड़ी 14 परियोजनाएं वर्ष 2003 से ही रुकी हुई हैं जिसके कारण इस क्षेत्र के गांवों में सिंचाई प्रभावित हो रही है।

चर्चा में क्यों :- भारत-बांग्लादेश के बीच दिसम्बर, 2019 में होने वाली संयुक्त नदी आयोग की बैठक को बांग्लादेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह बैठक भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित फेनी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित थी।

■ जैंडर गैप रिपोर्ट-2020

स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) ने दिसम्बर, 2019 में 153 देशों के आंकड़ों के आधार पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2020 (Gender Gap Report-2020) जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में भारत पिछले दो वर्षों से 108वें स्थान पर बना हुआ था। रिपोर्ट में आइसलैंड को सबसे कम लैंगिक भेदभाव वाला देश बताया गया। महिला स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत (150वां स्थान) इस रिपोर्ट में नीचे के पांच देशों में शामिल रहा। महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वां है।

■ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2019

दिसम्बर, 2019 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 में भारत ने अपनी रैंक में सुधार करते हुए 9वां स्थान प्राप्त किया है। कोई भी देश सूचकांक में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया है, इसलिए एक बार फिर पहले तीन स्थान रिक्त रहे। इस सूचकांक को मैड्रिड में आयोजित COP-25 के आयोजन के दौरान जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 में स्वीडन ने 75.77 अंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं इस सूचकांक में अमेरिका 18.60 अंक प्राप्त कर अंतिम स्थान पर है।

■ मानव विकास सूचकांक-2019

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) द्वारा दिसम्बर, 2019 में मानव विकास सूचकांक (Human development Index-HDI) 2019 जारी किया गया। सूचकांक के अनुसार 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भारत 130वें स्थान पर था।

शीर्ष पांच देश :-	
स्थान	**देश**
1	नार्वे
2	स्विट्जरलैंड
3	ऑस्ट्रेलिया
4	आयरलैंड
5	जर्मनी
निचले पायदान वाले देश :-	
स्थान	**देश**
129	नाइजर
128	दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य
127	दक्षिण सूडान
126	चाड
125	बुरुंडी

यह भी जानें:- मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक की गणना 4 प्रमुख संकेतकों- जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम:- UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है।

चर्चित स्थान

■ करतारपुर कॉरिडोर

पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब के लिए बने करतारपुर कॉरिडोर तथा यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवम्बर, 2019 को पंजाब के सुल्तानपुर लोधी जिले स्थित डेरा बाबा नानक में मत्था टेकने के बाद किया। पीएम मोदी ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को भी रवाना किया।

■ कालापानी

नेपाल ने भारत सरकार द्वारा 2 नवम्बर, 2019 को जारी भारत के नए राजनीतिक मानचित्र में उत्तराखंड के 'कालापानी' को भारतीय क्षेत्र में दर्शाए जाने पर आपत्ति जाहिर की है। नेपाल का तर्क है कि 'कालापानी' नेपाल के धारचुला जिले का हिस्सा है। वहीं, भारत का तर्क है कि नए नक्शे में नेपाल के साथ भारत की सीमा को किसी प्रकार से संशोधित नहीं किया गया है।

■ रानोंग बंदरगाह

भारत और थाईलैंड के रानोंग बंदरगाह (Ranong Port) के बीच आर्थिक सहयोग के लिए समझौते को नवम्बर, 2019 में अंतिम रूप दिया गया है। भारत और थाईलैंड के बीच नए समुद्री मार्ग को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड रानोंग पोर्ट को लॉजिस्टिक गेटवे के रूप में विकसित कर रहा है। इससे भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री यात्रा का समय 10-15 दिन से घटकर 7 दिन रह जाएगा। वर्तमान में मालवाहक जहाज, मलेशिया के रास्ते होते हुए कृष्णापट्टनम बंदरगाह से चोन बुरी में चबांग बंदरगाह और बैंकॉक के बैंकॉक बंदरगाह तक की यात्रा करते हैं।

■ कोझीकोड

सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए केरल के कोझीकोड में प्लास्टिक की बोतलों से दुनिया का पहला मरीन सिमिट्री (समुद्री कब्रिस्तान) बनाया गया है। इसका निर्माण कोझीकोड के बेपोर तट पर किया गया है।

■ व्हाइट आइलैंड

व्हाइट आइलैंड एक सक्रिय ऐंडेसाइट स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट से 30 मील की दूरी पर प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है। यह न्यूजीलैंड का सबसे सक्रिय शंकु ज्वालामुखी है जिसका लगभग 70% हिस्सा समुद्र के नीचे स्थित है।

चर्चा में क्यों:- दिसम्बर, 2019 में व्हाइट आइलैंड पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कुछ पर्यटकों की मौत हो गई।

■ सुलावेसी

इंडोनेशिया के द्वीप में दो साल पहले खोजी गई सुलावेसी की एक गुफा में 44 हजार साल पुराना एक भित्तिचित्र मिला है। शोधकर्त्ताओं का दावा है, 4.5 मीटर चौड़ा यह दुर्लभ भित्तिचित्र दुनिया के इतिहास में सबसे पुराना है। इस कलाकृति में गुफा की दीवार पर गहरे लाल रंग से एक सींग वाला जानवर बनाया गया है, जिसका एक शिकारी पीछा कर रहा है।

चर्चित व्यक्ति

■ अनीता आनंद

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने नवम्बर, 2019 में केबिनेट में भारतीय मूल की अनीता इंदिरा आनंद को शामिल किया है। कनाडा की केबिनेट में शामिल होने वाली वे पहली हिन्दू हैं।

■ परवेज मुशर्रफ

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को वहां की एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में 17 दिसम्बर, 2019 को फांसी की सजा सुनाई है। मुशर्रफ पर वर्ष 1999 में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट व वर्ष 2007 में आपातकाल घोषित करने का आरोप है।

■ क्रिस्टीना कोच

नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। फ्लाइट इंजीनियर क्रिस्टीना ने दिसम्बर, 2019 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 288 दिनों तक रहने का नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेगी व्हिट्सन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

■ रॉय जॉर्जन स्वेनिंगसेन

कनाडा के रॉय जॉर्जन स्वेनिंगसेन 'अंटार्कटिक आइस मैराथन' को पूरा करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। स्वेनिंगसेन की आयु 84 वर्ष है। उन्होंने इस दौड़ को 11 घंटे, 41 मिनट और 58 सेकण्ड में पूरा किया।

नियुक्ति

■ गोतबाया राजपक्सा

श्रीलंका के पूर्व रक्षा मंत्री एवं 'श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट' के गोतबाया राजपक्सा ने 18 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने इस पद पर मैत्रीपाल सिरिसेना का स्थान लिया है।

■ महिंदा राजपक्सा

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्सा ने अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्सा को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है।

गोतबाया ने महिंदा को 21 नवम्बर, 2019 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने इस पद पर रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। महिंदा अगस्त 2020 में होने वाले आम चुनाव तक कार्यवाहक केबिनेट के प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

■ राफेल मारियानो ग्रॉसी

अर्जेन्टीना के राफेल मारियानो ग्रॉसी को नवम्बर, 2019 में 'अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण' का नया महानिदेशक चुना गया है। वह इस पद पर जापान के युकिया अमानो का स्थान लेंगे, जिनका जुलाई, 2019 में निधन हो गया था।

यह भी जानें:- अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण' का गठन 29 जुलाई, 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है और इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 171 है। यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकता है।

■ मैनुएल मरेरो क्रूज

उत्तरी अमेरिकी देश क्यूबा में 43 साल बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज केनेल ने पर्यटन मंत्री मैनुएल मरेरो क्रूज को 22 दिसम्बर, 2019 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 में तत्कालीन नेता फिदेल कास्त्रो ने प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया था।

■ अशरफ गनी

अशरफ गनी को पुनः अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। अफगानिस्तान में 28 सितम्बर, 2019 को चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम 22 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया। चुनाव में अशरफ गनी को 50.64 फीसदी व उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला को 39.52 फीसदी मत मिले।

■ पृथ्वीराज सिंह

पृथ्वीराज सिंह रूपन ने 2 दिसम्बर, 2019 को मॉरीशस के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। मॉरीशस में राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है, हालांकि सरकार में उसकी कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होती।

■ प्रविन्द्र जुगनाथ

मॉरीशस में प्रविन्द्र जुगनाथ ने पुनः प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया है। वहां, नवम्बर, 2019 में चुनाव हुए थे। मॉरीशस में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

■ सना मारिन

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता सना मारिन ने 10 दिसम्बर, 2019 को फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे फिनलैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस पद पर एंटी रिने का स्थान लिया।

■ सुन्दर पिचाई

गूगल ने दिसम्बर, 2019 में भारतीय मूल के सुन्दर पिचाई को अपनी मूल कम्पनी 'अल्फाबेट इंक' का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद कम्पनी ने यह निर्णय किया। गौरतलब है कि पिचाई वर्ष 2015 में गूगल के सीईओ बने थे।

■ चार्ल्स मिशेल

बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। 751 सदस्यों वाली यूरोपीय संसद में उनके नाम को बहुमत का समर्थन मिला। इस निकाय में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता उस सदस्य देश का प्रतिनिधि करता है जिसके पास उस समय यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता होती है। मिशेल ने इस पद पर एलन टस्क का स्थान लिया।

निधन

■ जॉर्ज जोसेफ लॉर

यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड (बारकोड) की खोज करने वाले जॉर्ज जोसफ लॉर का 5 दिसम्बर, 2019 को निधन हो गया।

पुरस्कार

■ इटैलियन गोल्डन सैंड आर्ट अवॉर्ड

ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को वर्ष 2019 का इटैलियन गोल्डन सैंड आर्ट अवॉर्ड-2019 प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार नवम्बर, 2019 में इटली में आयोजित समारोह में दिया गया।

■ ग्रेटा थनबर्ग को अन्तरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार

स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को 20 नवम्बर, 2019 को अन्तरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से

सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए दिया गया है। थनबर्ग के साथ-साथ कैमरून की 15 वर्षीय शांति कार्यकर्ता डिविना मलौम को भी अन्तरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है।

■ गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए 20 दिसम्बर, 2019 को 'गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार' शुरू करने की घोषणा की। यह पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाएगा। प्रथम वर्ष के लिए यह पुरस्कार पशु कल्याण के लिए समर्पित होगा।

■ डैनी काये मानवाधिकार पुरस्कार

भारत की प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ की ओर से 3 दिसम्बर, 2019 को डैनी काये मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार एन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन के क्षेत्र में काम के लिए दिया गया।

■ मिस यूनिवर्स

जॉर्जिया के अटलांटा में 8 दिसम्बर, 2019 को आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी टूंजी (26) को मिस यूनिवर्स चुना गया। वर्ष 2018 की मिस यूनिवर्स फिलीपींस की कैट्रियोना ग्रे ने उन्हें ताज पहनाया। प्रतियोगिता में भारत सहित 90 देशों की सुन्दरियों ने भाग लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व लखनऊ की वर्तिका सिंह ने किया। गौरतलब है कि भारत की ओर से अब तक सुष्मिता सेन वर्ष 1994 व लारा दत्ता वर्ष 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं।

■ मिस वर्ल्ड

ब्रिटेन के लंदन में 14 दिसम्बर, 2019 को हुए फाइनल मुकाबले में जमैका की टोनी एन. सिंह (26) को मिस वर्ल्ड चुना गया। वर्ष 2018 की मिस वर्ल्ड वेनेसा पॉस डि लियोन ने उन्हें ताज पहनाया। प्रतियोगिता में भारत सहित 111 देशों की सुन्दरियों ने भाग लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान की सुमन राव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सुमन जून, 2019 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड चुनीं गई थीं।

■ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर-2019

स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग (16) को अमेरिका की टाइम पत्रिका ने वर्ष 2019 के लिए 'पर्सन ऑफ द ईयर' घोषित किया है।

■ ITF के वर्ल्ड चैम्पियन-2019

टेनिस के संचालन की वैश्विक संस्था इंटरनेशनल टेनिस फैडरेशन (ITF) ने स्पेन के राफेल नडाल को पुरुषों में तथा ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी को महिलाओं में वर्ष 2019 का विश्व चैम्पियन घोषित किया है। यह पुरस्कार पेरिस में जून, 2020 में होने वाले आईटीएफ विश्व चैम्पियन कार्यक्रम में वितरित किए जाएंगे।

ये रहे विजेता:-

- **पुरुष एकल** - राफेल नडाल (स्पेन)
- **महिला एकल** - एश्ले बार्टी (ऑस्ट्रेलिया)
- **पुरुष युगल** - जुआन सेबेस्टियन (कोलंबिया) व रॉबर्ट फराह (कोलंबिया)
- **महिला युगल** - टीमिया बाबोस (हंगरी) व क्रिस्टीना म्लादेनोविक (फ्रांस)

■ WTP अवॉर्ड-2019

महिला टेनिस संघ (WTP) द्वारा 11 दिसम्बर, 2019 को डब्ल्यूटीपी प्लेयर अवॉर्ड की घोषणा की गई। ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया।

■ क्रिस्टल अवॉर्ड

विश्व आर्थिक मंच की ओर से वार्षिक 26वें क्रिस्टल अवॉर्ड की घोषणा 13 दिसम्बर, 2019 को की गई। इस पुरस्कार के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, ऑस्ट्रेलियाई कलाकार लिनेट वालवर्थ, चीन की जिन जिंग तथा अमेरिका के थिएस्टर गेट्स को चुना गया है। दीपिका को यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए दिया जाएगा।

■ विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरस्कार

विश्व बैडमिंटन महासंघ के वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए पुरस्कारों का वितरण 9 दिसम्बर, 2019 को चीन के गुआंगझू में किया।

ये रहे प्लेयर ऑफ द ईयर:-

- **पुरुष एकल** - कैंटो मोमोटा (जापान)
- **महिला एकल** - हुआंग या क्विओंग (चीन)
- **पैरा बैडमिंटन में पुरुष एकल** - क्यू जिमो (चीन)
- **पैरा बैडमिंटन में महिला एकल** - लियानी रात्रि ओक्तिला (इंडोनेशिया)

■ महिला क्रिकेट : आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार

महिला क्रिकेटरों के लिए आईसीसी के वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा 17 दिसम्बर, 2019 को की गई।

ये रहे विजेता:-

- **वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर (राचेल हेयो फ्लिंट अवॉर्ड)** - एलिसे पेरी (ऑस्ट्रेलिया)
- **वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर** - एलिसे पेरी (ऑस्ट्रेलिया)
- **वुमेन्स टी-20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर** - एलिसे हिली (ऑस्ट्रेलिया)
- **वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर** - चानिंडा सुथिरूआंग (थाइलैंड)

■ वर्ल्ड हैबिटेट अवॉर्ड

ओडिशा सरकार को 'JAGA Mission' के लिए दिसम्बर, 2019 में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड प्रदान किया गया।

JAGA Mission :- ओडिशा सरकार ने 7 मई, 2018 को JAGA Mission की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य 'आत्म-सम्मान और बेदखली के सतत भय से मुक्ति' देने के वादे के तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले एक लाख शहरी गरीबों को लाभान्वित करना है।

यह भी जानें :- वर्ल्ड हैबिटेट अवाड्र्स की स्थापना वर्ष 1985 में बिल्डिंग एंड सोशल हाउसिंग फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार वर्ल्ड हैबिटेट (यूके में स्थित) द्वारा यूएन-हैबिटेट (UN-Habitat) के साथ मिलकर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार दुनिया भर से अभिनव, उत्कृष्ट और क्रांतिकारी आवासीय विचारों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान स्वरूप प्रदान किया जाता है।

■ अमिताभ बागची को डीएससी पुरस्कार-2019

अमिताभ बागची को उनके उपन्यास 'हाफ द नाइट इज गॉन' के लिए दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए डीएससी पुरस्कार-2019 से सम्मानित किया गया है। यह दक्षिण एशिया की संस्कृति, राजनीति, इतिहास या लोगों के बारे में किसी भी जाति या राष्ट्रीयता पर लेखन के लिए लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

यह भी जानें :- दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार की स्थापना 2010 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 25000 डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार बुनियादी ढांचा कंपनी डीएससी ग्रुप द्वारा वित्तपोषित है।

■ एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवॉर्ड

जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म 'गली बॉय' को एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवाड्र्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले फिल्म को 92वें ऑस्कर अकादमी अवाड्र्स के लिए भी नामांकन किया गया है।

■ लियोन मेसी को बैलन डि ओर अवॉर्ड

अर्जेंटीना के दिग्गज स्ट्राइकर लियोन मेसी ने छठी बार प्रतिष्ठित बैलन डि ओर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। मेसी विश्व में सबसे ज्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में लियोन मेसी ने दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है। फ्रांस फुटबॉल मैगजीन द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड के लिए विश्व के 30 खिलाड़ियों को नामित किया था।

■ गोल्डन टारगेट अवॉर्ड

भारत की निशानेबाज एलावेनिल वालारिवान को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने वर्ष 2019 में 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्द्धा में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन टारगेट अवॉर्ड से नवाजा है। उनके अलावा जयपुर के राइफल शूटर दिव्यांश सिंह पंवार को भी गोल्डन टारगेट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। दुनिया का नंबर-1 निशानेबाज बनने पर उन्हें यह अवॉर्ड दिया गया।

चर्चित पुस्तकें

- **नो वन इज टू स्मॉल टु मेक ए डिफरेंस** - ग्रेटा थुनबर्ग
- **माइंड मास्टर्स** - विश्वनाथन आनंद
- **हाफ द नाइट इज गॉन** - अमिताभ बागची
- **द डिजेनरेशन ऑफ इंडिया** - टी.एन. शेषन
- **ए हर्टफुल ऑफ बर्डन** - टी.एन. शेषन
- **कागज की नाव** - नासिरा शर्मा
- **अस्ति और भवति** - डॉ.विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
- **छीलते हुए अपने को** - नन्दकिशोर आचार्य
- **एन इरा ऑफ डार्कनेस** - शशि थरूर
- **बारीक बात** - रामस्वरूप किसान
- **ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर-मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ** - सुशील कुमार

प्रमुख दिवस/सप्ताह/वर्ष

नवम्बर

- 05 नवम्बर – विश्व सुनामी जागरूकता दिवस
- 07 नवम्बर – राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
- 09 नवम्बर – राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस
- 10 नवम्बर – शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस
- 11 नवम्बर – राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
- 16 नवम्बर – राष्ट्रीय प्रेस दिवस
- 19 नवम्बर – विश्व शौचालय दिवस
- 25 नवम्बर – महिलाओं के खिलाफ अन्तरराष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस
- 26 नवम्बर – संविधान दिवस
- 14-20 नवम्बर – राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह
- 19-25 नवम्बर – विश्व धरोहर सप्ताह

दिसम्बर

- 01 दिसम्बर – विश्व एड्स दिवस
- 02 दिसम्बर – विश्व कम्प्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अन्तरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस
- 03 दिसम्बर – अन्तरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस
- 04 दिसम्बर – नौसेना दिवस
- 05 दिसम्बर – विश्व मृदा दिवस
- 06 दिसम्बर – नागरिक सुरक्षा दिवस
- 09 दिसम्बर – अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस
- 10 दिसम्बर – मानवाधिकार दिवस
- 11 दिसम्बर – अन्तरराष्ट्रीय पर्वत दिवस
- 12 दिसम्बर – अन्तरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस
- 14 दिसम्बर – राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
- 18 दिसम्बर – अन्तरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस
- 20 दिसम्बर – अन्तरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस
- 23 दिसम्बर – राष्ट्रीय किसान दिवस
- 25 दिसम्बर – राष्ट्रीय सुशासन दिवस
- 09-14 दिसम्बर – राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष

- वर्ष 2020 – पौधों के स्वास्थ्य हेतु अन्तरराष्ट्रीय वर्ष
- वर्ष 2021 – शांति एवं विश्वास हेतु अन्तरराष्ट्रीय वर्ष
- वर्ष 2022 – कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्यपालन हेतु अन्तरराष्ट्रीय वर्ष

2 राष्ट्रीय घटनाक्रम

■ सीजेआई भी आरटीआई के दायरे में

सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने 13 नवम्बर, 2019 को निर्णय दिया कि आरटीआई अधिनियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण है। पीठ ने फैसले में यह भी कहा कि आरटीआई का उपयोग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के लिए नहीं किया जाएगा, जब भी पारदर्शिता की बात होगी, न्यायिक स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाएगा।

पीठ में ये शामिल:- सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस संजीव खन्ना।

■ गुरु नानक की 550वीं जयंती

12 नवम्बर, 2019 (कार्तिक पूर्णिमा) को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। गुरु नानक का जन्म वर्ष 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को ननकाना साहिब (वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है) में हुआ था। गुरु नानक देव 10 सिख गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे।

■ बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन

भारत के जहाजरानी मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 2019 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पहले 'बिम्सटेक बंदरगाह' सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आयात-निर्यात तथा तटीय जहाजरानी को प्रोत्साहित कर आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावना तलाशना है।

बिम्सटेक :- बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और आस-पास के सात देश (भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान व नेपाल) शामिल हैं। यह संगठन क्षेत्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करता है। बिम्सटेक का उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों और भौगोलिक लाभ का उपयोग करके आम हित के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग से व्यापार में तेजी लाना तथा विकास को गति देना है।

■ ऑपरेशन मां

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन माँ के माध्यम से इस वर्ष लगभग 50 युवक, आतंकी संगठनों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। यह ऑपरेशन सेना के चिनार कोर द्वारा चलाया गया। यह एक प्रकार का मानवीय ऑपरेशन है जिसके अंतर्गत घरों से लापता हुए युवाओं का पता लगाकर और उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें वापस घर लाना था।

■ भारतीय पोषण कृषि कोष

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 18 नवम्बर, 2019 को भारतीय पोषण कृषि कोष की शुरुआत की है। इस परियोजना को बिल एंड मिलिडा फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करने के लिए बहुक्षेत्रीय ढांचा विकसित करना है। इसके तहत बेहतर पोषक उत्पाद हेतु 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों पर जोर दिया जाएगा।

■ राज्यपालों का 50वां सम्मेलन

राज्यपालों का 50वां सम्मेलन 23-24 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन में जनजातीय कल्याण, जल, कृषि, उच्च शिक्षा एवं जीवन की सुगमत पर बल दिया गया।

■ लोकपाल को मिला प्रतीक चिह्न व ध्येय वाक्य

भ्रष्टाचार रोधी संस्थान 'लोकपाल' ने 26 नवम्बर, 2019 को अपना प्रतीक चिह्न व ध्येय वाक्य लॉन्च किया। ईशोपनिषद के श्लोक 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम्' को ध्येय वाक्य के रूप में चुना गया है जिसका अर्थ है 'किसी के धन का लोभ न करो'। वहीं, यूपी के इलाहाबाद निवासी प्रशांत मिश्र के डिजाइन को लोकपाल का प्रतीक चिह्न चुना गया है।

यह भी जानें:-लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 के तहत गठित लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च, 2019 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को प्रथम लोकपाल के रूप में शपथ दिलाई थी।

■ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

28 नवम्बर, 2019 को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। विधानसभा के विशेष सत्र में 30 नवम्बर को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (शिवसेना-राकांपा और कांग्रेस) सरकार ने 169 वोटों से विश्वास मत हासिल किया।

नाटकीय रहा घटनाक्रम:-गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर, 2019 में हुए चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इस बीच एनसीपी के अजीत पवार भाजपा से मिल गए और भाजपा के देवेन्द्र फणनवीस को राज्यपाल भगत सिंह ने मुख्यमंत्री व अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शिवसेना, एनसीपी व कांग्रेस द्वारा इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिस पर न्यायालय ने भाजपा को विधानसभा में तत्काल खुले में मतदान द्वारा बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया। विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने से पूर्व ही मुख्यमंत्री फणनवीस व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने त्यागपत्र दे दिया। फणनवीस के त्यागपत्र के बाद 'महाराष्ट्र विकास अघाड़ी' (शिवसेना, एनसीपी व कांग्रेस) ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

■ युवाह पहल

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नवम्बर, 2019 में यूनिसेफ द्वारा चलाई गई 'युवाह पहल' को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य 10-24 वर्ष के किशोरों हेतु शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि विश्व के किशोरों की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत भारत में निवास करता है। भारत इस प्रकार की पहल की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश है। यह पहल वर्ष 2018 में न्यूयॉर्क में हुए 'ग्लोबल जनरेशन अनलिमिटेड' आंदोलन से संबंधित है।

■ भारतीय पोषण एंथेम

उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने 3 दिसम्बर, 2019 को 'भारतीय पोषण एंथेम' लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2022 तक कुपोषण से मुक्त करना है। यह एंथेम गीतकार प्रसून जोशी ने लिखा है और शब्द शंकर महादेवन के हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को वर्ष 2020 तक कुपोषण मुक्त करने के लिए मार्च, 2018 में 'पोषण अभियान' मिशन की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों को पर्याप्त पोषण व सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करना है।

■ अबेरदीन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना

गृह मंत्रालय ने दिसम्बर, 2019 में देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है। इस सूची में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अबेरदीन पुलिस थाना संपत्ति विवाद, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ अपराध से निपटने के मामलों में पहले स्थान पर है। देश के 15,500 पुलिस थानों में से 10 पुलिस थानों की रैंकिंग डाटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष निरीक्षण और जनता के फीडबैक के आधार पर की गई है।

टॉप-10 थाने:-

रैंकिंग	थाना	स्थान
1	अबेरदीन	अंडमान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
2	बालासिनोर	माहीसागर (गुजरात)
3	एजेके बुरहानपुर	बुरहानपुर (मध्य प्रदेश)
4	एडब्ल्यूपीएस थेनी	थेनी (तमिलनाडु)
5	अनिनि	दिबांग घाटी (अरुणाचल प्रदेश)
6	बाबा हरिदास नगर, द्वारका	दक्षिण-पश्चिम जिला (दिल्ली)
7	**बकानी**	**झालावाड (राजस्थान)**
8	चोप्पाडंडी(एम)	करीमनगर (तेलंगाना)
9	बिकोलीम	उत्तर गोवा (गोवा)
10	बरगावा	शिवपुर (मध्य प्रदेश)

■ अटल भूजल योजना

निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए 25 दिसम्बर, 2019 को 'अटल भूजल योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना का कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए है तथा यह पांच वर्षों की अवधि (2020-21 से 2024-25) के लिए लागू की जाएगी। 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। बकाया 50 प्रतिशत नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनभागीदारी के माध्यम से भू-जल प्रबंधन में सुधार लाना है। इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

■ भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिलनगर खंड में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां थर्ड जेंडर के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

■ सुशासन सूचकांक

25 दिसम्बर, 2019 को 'सुशासन दिवस' के अवसर पर 'कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय' द्वारा सुशासन सूचकांक (Good Governance Index- GGI) की शुरुआत की गई है।

बड़े राज्यों की रैंकिंग :-

शीर्ष स्थान वाले तीन राज्य: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक।

निचले स्थान वाले तीन राज्य : ओडिशा, बिहार, गोवा।

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की रैंकिंग:-

- **शीर्ष स्थान वाले तीन राज्य :**

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा।

- **निचले स्थान वाले तीन राज्य:**

अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मेघालय।

केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग :-

- **शीर्ष तीन राज्य :-** पांडिचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली।
- **निचले स्थान पर:** लक्षद्वीप।

■ भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2019

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दिसम्बर, 2019 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2019 जारी की गई है। वर्ष 1987 से हर दूसरे साल यह रिपोर्ट जारी की जा रही है। यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है।इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

प्रमुख तथ्य:-

- **देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल**
  8,07,276 वर्ग किमी.
  (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56%)
- **कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र**
  7,12,249 वर्ग किमी.
  (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%)
- **कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र**
  95,027 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89%)
- **वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि**
  3,976 वर्ग किमी. (0.56%)
- **वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि**
  1,212 वर्ग किमी. (1.29%)
- **वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि**
  5,188 वर्ग किमी. (0.65%)

वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आँकड़े:

सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य:

मिजोरम	85.41%
अरुणाचल प्रदेश	79.63%
मेघालय	76.33%
मणिपुर	75.46%
नगालैंड	75.31%

सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य:

मध्य प्रदेश	77,482 वर्ग किमी.
अरुणाचल प्रदेश	66,688 वर्ग किमी.
छत्तीसगढ़	55,611 वर्ग किमी.
ओडिशा	51,619 वर्ग किमी.
महाराष्ट्र	50,778 वर्ग किमी.

वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य:

कर्नाटक	1,025 वर्ग किमी.
आंध्र प्रदेश	990 वर्ग किमी.
केरल	823 वर्ग किमी.
जम्मू-कश्मीर	371 वर्ग किमी.
हिमाचल प्रदेश	334 वर्ग किमी.

■ आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां

आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 27 दिसम्बर, 2019 को राज्य की राजधानी को तीन अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय किया। नई घोषणा के अनुसार, निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और कर्नूल न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित हो सकती है।

भारत के एक से अधिक राजधानी वाले अन्य राज्य:- महाराष्ट्र की दो राजधानियां मुंबई और नागपुर हैं। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां शिमला और धर्मशाला (शीतकालीन) हैं। पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर की दो राजधानियां श्रीनगर एवं जम्मू (शीतकालीन) थीं।

चर्चित स्थान

■ सिसेरी पुल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 नवम्बर, 2019 को अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया। 200 मीटर लम्बा यह पुल जोनाई-पासीघाट-राणाघाट-रोइंग सड़क के बीच बना है। यह दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ता है। इस पुल के बन जाने से पासीघाट से रोइंग की यात्रा में लगने वाले समय में लगभग पांच घंटे की कमी आ जाएगी।

■ विलिंग्डन द्वीप

विलिंग्डन द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। यह केरल की वेम्बनाद झील का ही एक हिस्सा है। यह कोच्चि बंदरगाह के साथ-साथ भारतीय नौसेना की कोच्चि नौसेना बेस के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

चर्चा में क्यों:- भारतीय नौसेना द्वारा कोच्चि स्थित विलिंग्डन द्वीप पर नवम्बर, 2019 में फिट इंडिया और गो ग्रीन नामक दो पहलों का आयोजन किया गया।

■ महादयी नदी

महादयी नदी गोवा राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। पणजी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के बेलगाम जिले के खानपुर नामक स्थान से होता है। गोवा में प्रवेश करने के बाद इसमें कई धाराएं मिलती हैं जिसके बाद यह मंडोवी के नाम से जानी जाती है। लगभग 111 किमी लंबी इस नदी का दो-तिहाई भाग गोवा में है। गोवा की अन्य नदियां लवणीय जल वाली हैं, वहीं मंडोवी जो एक मीठे जल का स्रोत होने के साथ-साथ जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी और मछली पालन का भी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

चर्चा में क्यों:- महादयी नदी पर प्रस्तावित कलासा बंदूरी परियोजना का गोवा राज्य द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य महादयी नदी के पानी का डायवर्जन करके उसे उत्तरी कर्नाटक के तीन जिलों में पहुंचाना है।

■ कालापानी क्षेत्र

भारत द्वारा हाल ही में जारी नए राजनीतिक मानचित्र में कालापानी क्षेत्र (Kalapani Territory) की सीमा को लेकर नेपाल ने औपचारिक विरोध किया है। कालापानी क्षेत्र भारतीयों के एक तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। यह काली नदी का उद्गम स्थल भी है। यही काली नदी कालापानी से भारत और नेपाल दोनों देशों का सीमांकन करती है जो आगे चलकर टनकपुर में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है।

■ अटल सुरंग

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसम्बर, 2019 को सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे की रणनीतिक सुरंग का नाम 'अटल सुरंग' रखा है।

यह भी जानें:- 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। यह सुरंग पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरेगी। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी करेगी और परिवहन लागत में करोड़ों रुपए की बचत करेगी। इस सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को सदैव कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो शीत ऋतु के दौरान लगभग 6 महीने तक लगातार शेष देश से कटे रहते हैं।

■ मुल्लापेरियार बांध

मुल्लापेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। इसके द्वारा तमिलनाडु राज्य अपने पांच दक्षिणी जिलों के लिए पीने के पानी और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पूर्व की ओर मोड़ना है।

चर्चा में क्यों :- जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्लापेरियार बांध से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए दिसम्बर, 2019 में तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है।

पेरियार नदी: पेरियार नदी 244 किलोमीटर की लंबाई के साथ केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसे 'केरल की जीवनरेखा' के रूप में भी जाना जाता है। यह नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और 'पेरियार राष्ट्रीय उद्यान' से होकर बहती है।

चर्चित व्यक्ति

■ जी.एस.लक्ष्मी

भारत की जी.एस.लक्ष्मी ने 8 दिसम्बर, 2019 को यूएई के शारजाह में पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 की तीसरी सीरीज में यूएई-अमेरिका के मैच में रैफरी की भूमिका निभाई। विदेश में किसी पुरुष वन-डे इंटरनेशनल मैच में रैफरी की भूमिका निभाने वाली वे पहली महिला हैं।

■ डेजी बोटर्स

सूरीनाम के राष्ट्रपति डेजी बोटर्स को स्थानीय सैन्य अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें वर्ष 1982 में 15 लोगों को गोली से मरवाने का दोषी पाया।

■ शिवांगी स्वरूप

बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप नौसेना में पायलट नियुक्त हुई हैं। यह मुकाम पाने वाली वे पहली महिला हैं। शिवांगी ने 2 दिसम्बर, 2019 को प्रशिक्षण पूरा कर कोच्चि के नेवल बेस पर ऑपरेशनल ड्यूटी ज्वॉइन की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में ही लेफ्टिनेंट भावना कांत भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी थीं।

नियुक्तियां

■ चिराग पासवान

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने 5 नवम्बर, 2019 को चिराग पासवान को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। चिराग केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास पासवान ने वर्ष 2000 में लोजपा का गठन किया था, जिसका जनाधार मुख्य रूप से बिहार का दलित जनसमुदाय है।

■ प्रकाश जावडेकर

शिवसेना के अरविंद सावंत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का पदभार भी सौंपा गया है।

■ गिरीश चन्द्र मुर्मू

गिरीश चन्द्र मुर्मू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

■ राधा कृष्ण माथुर

राधा कृष्ण माथुर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

■ सुनील शेट्टी

बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नाडा ने 10 दिसम्बर, 2019 को इसकी घोषणा की।

नाडा :- वर्ष 2009 में स्थापित राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) देश में अपने सभी रूपों में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। इसके प्रमुख दायित्वों में विश्व एंटी डोपिंग कोड के अनुरूप एंटी डोपिंग नियमों और नीतियों को अपनाना तथा कार्यान्वित करना, खेल संगठनों और अन्य डोपिंग विरोधी संगठनों के साथ सहयोग करना, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संगठनों के बीच पारस्परिक परीक्षण को प्रोत्साहित करना तथा एंटी डोपिंग अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है।

■ ले.जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को देश का नया थलसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 31 दिसम्बर, 2019 को इस पद से सेवनिवृत्त जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है। उल्लेखनीय है कि देश के थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति केबिनेट की 'अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द केबिनेट' करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व रक्षा मंत्री शामिल होते हैं।

■ न्यायमूर्ति एन.वी.रमन्ना

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी.रमन्ना को दिसम्बर, 2019 में 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर न्यायमूर्ति एस.ए.बोबड़े का स्थान लिया है।

■ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसम्बर, 2019 में देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff- CDS) के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी। यह भारत की जल, थल एवं वायु सेना के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा व आपस में उनका संपर्क स्थापित करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs& DMA) का भी प्रमुख होगा।

निधन

■ टी.एन. शेषन

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन (87) का 10 नवम्बर, 2019 को चेन्नई में निधन हो गया। वे 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके द्वारा ही देश में मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1996 में उन्हें सरकारी सेवा के लिए 'रेमन मैग्सेसे पुरस्कार' से नवाजा गया था। 'द डिजेनरेशन ऑफ इंडिया' व 'ए हर्टफुल ऑफ बर्डन' उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं।

■ रमाकांत गुंदेचा

ध्रुपद उस्ताद रमाकांत गुंदेचा (57) का 8 नवम्बर, 2019 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था।

ध्रुपद:- ध्रुपद शास्त्रीय संगीत की एक प्राचीन श्रेणी है। इसके विकास में संगीत सम्राट तानसेन एवं उनके गुरु स्वामी हरिदास का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके प्रमुख गायकों में डागर बंधु, गुंदेचा बंधु, पंडित रामचतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी आदि शामिल हैं। इसे गाते समय कंठ और फेफड़ों पर अधिक जोर दिया जाता है और पुरुष ही इसे गा सकते हैं, इसलिए इसे मर्दाना गायकी भी कहा जाता है। वर्तमान में कुछ महिलाओं ने भी इसे गाने की शुरुआत की है जिसमें भारत की अमिता सिन्हा महापात्रा और पाकिस्तान की आलिया राशिद प्रमुख हैं।

■ एडमिरल सुशील कुमार

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार (79) का 27 नवम्बर, 2019 को निधन हो गया। वे वर्ष 1998-2001 तक भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे थे। उन्होंने पुस्तक 'ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर- मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ' लिखी।

पुरस्कार

■ व्यास सम्मान

के.के.बिड़ला फाउंडेशन का व्यास सम्मान-2019(29वां) हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उपन्यास 'कागज की नाव' के लिए प्रदान किया गया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिह्न प्रदान किया गया। 28वां व्यास सम्मान हिंदी के लेखक लीलाधर जुगूड़ी को उनके कविता संग्रह 'जितने लोग उतने प्रेम' के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई।

■ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

शांति, नि:शस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ब्रिटेन के डेविड एटनबरो को प्रदान किया जाएगा। डेविड को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा 19 नवम्बर, 2019 को की गई। इससे पूर्व वर्ष 2018 का यह पुरस्कार सेन्टर फॉर साइंस एंड एनवायर्नमेंट को व 2017 का पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया था।

यह भी जानें:- भारत सरकार के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। यह अन्तरराष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार है, जो समाजसेवा, नि:शस्त्रीकरण अथवा विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

■ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड

सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड-2019 का वितरण 3 नवम्बर, 2019 को मुम्बई में आयोजित एक समोराह में किया गया। इस वर्ष की थीम थी 'Combating Contemporary forms of slavery'।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता:- 1. कैलाश सत्यार्थी, 2. अजीत सिंह, 3. दाफोह (यूएसए), 4. फ्री ए गर्ल, 5. हसीना खारभिह, 6. जीविका, 7. अलेजेंद्रा रसेल, 8. ऑफिस फॉर द रेस्क्यू ऑफ यजीदीज, 9. प्रेरणा, 10. रॉब विलियम्बस, 11. जूनियर नजिता नसुआमी, 12. रॉबर्ट बिल्हीमेर।

■ अन्तरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

भारत का 50वां अन्तरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (International Film Festival of India-IFFI) 20-28 नवम्बर, 2019 को गोवा के पणजी में सम्पन्न हुआ। इस दौरान 76 देशों की 200 से ज्यादा फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव का फोकस देश रूस था। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म 'डेस्पाइट द फॉग' व समापन फिल्म 'मार्घे एंड हर मदर' रही। अन्तराष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष अमेरिका के जॉनइरा वेली थे।

इन्हें मिले पुरस्कार:-

- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 'गोल्डन पीकॉक अवार्ड'** - पार्टीकल
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक** - भारत के लिजो जोस पेलिसरी को मलयालमी फिल्म 'जल्लीकट्टू' के लिए
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता** - सेउ जार्ज
- **लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड** - फ्रांस की अभिनेत्री इजावेली एनी मेडेलिन हपर्ट
- **आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवॉर्ड** - रजनीकांत
- **जूरी का विशेष पुरस्कार** - पेमा त्सेडेन को उनकी फिल्म 'बेलून' के लिए
- **ICFI यूनेस्को गांधी मेडल** - रवांडा (रिकॉर्डो सेल्वेची द्वारा निर्देशित फिल्म)
- **ICFI यूनेस्को फेलिनी पुरस्कार** - IFFI को स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर

■ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2018

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने दिसम्बर, 2019 में नई दिल्ली में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्ष 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए।

ये रहे विजेता:-

श्रेणी	विजेता
◆ **सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म**	अंधाधुंध
◆ **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (साझा)**	आयुष्मान खुराना (अंधाधुंध) विक्की कौशल (उरी)
◆ **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री**	कीर्ति सुरेश
◆ **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक**	आदित्य धर (उरी)
◆ **सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक**	संजय लीला भंसाली
◆ **सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रैंडली राज्य**	उत्तराखंड
◆ **सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म**	टर्टल

इसके अलावा मराठी फिल्म 'नाल' को निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 'इंदिरा गांधी पुरस्कार', मराठी फिल्म 'पानी' को पर्यावरण संरक्षण पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, कन्नड़ फिल्म ओंडाला इराडाला को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार प्रदान किया गया।4

■ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार-2019

जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 19 नवम्बर, 2019 को 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार-2019' का वितरण किया गया।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता:-

- शीर्ष तीन राज्य:- 1.तमिलनाडु, 2.हरियाणा, 3.गुजरात
- शीर्ष तीन जिले:- 1.पेडापल्ली (तेलंगाना), 2.फरीदाबाद (हरियाणा), 3.रेवाड़ी (हरियाणा)।
- अधिकतम जन भागीदारी वाला राज्य:- 1. उत्तर प्रदेश

■ मूर्ति देवी पुरस्कार-2019

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 2019 का मूर्तिदेवी पुरस्कार (33वां) साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं हिन्दी के कवि डॉ.विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें आत्मकथा 'अस्ति और भवति' के लिए दिया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी भी लेखक को उनकी कृति के लिए दिया जाता है, जिनसे भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के मानवीय मूल्य प्रदर्शित होते हैं। पुरस्कार स्वरूप 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

■ साहित्य अकादमी पुरस्कार

वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा 18 दिसम्बर को की गई। इस पुरस्कार हेतु विभिन्न भाषाओं की 23 कृतियों का चयन किया गया है। नेपाली भाषा के लिए पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। हिन्दी भाषा में यह पुरस्कार **राजस्थान निवासी** नन्दकिशोर आचार्य को उनके काव्य संग्रह 'छीलते हुए अपने को' के लिए प्रदान किया जाएगा। वहीं, अंग्रेजी भाषा के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर को 'एन इरा ऑफ डार्कनेस' के लिए दिया जाएगा। पुरस्कारों का वितरण 25 फरवरी, 2020 को होगा। राजस्थानी भाषा के लिए यह पुरस्कार रामस्वरूप किसान को उनके कहानी संग्रह 'बारीक बात' के लिए दिया जाएगा।

■ नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार

केरल की नर्स लिनी पीएन को मरणोपरांत राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार-2019 से सम्मानित किया गया है। लिनी की वर्ष 2018 में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान एक मरीज का इलाज करते समय संक्रमण से मृत्यु हो गई थी।

यह भी जानें:- भारत सरकार ने वर्ष 1973 में नर्सों द्वारा प्रदान की जाने वाली सराहनीय सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के तौर पर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार की स्थापना की। इस पुरस्कार में 50,000 रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र, एक प्रशस्ति-पत्र और पदक दिया जाता है।

3 राजस्थान घटनाक्रम

■ उच्च न्यायालय के वार्ड कमेटियां बनाने के निर्देश

राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिकाओं में 'राजस्थान नगरपालिका एक्ट-2009' की धारा 54 के तहत प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। एक्ट की धारा 54 के तहत वार्ड में आम व्यक्तियों की पांच सदस्यीय कमेटी बनाने का प्रावधान है। इन कमेटियों का उद्देश्य पालिकाओं के रोजमर्रा के काम में आम नागरिकों की अधिकतम भूमिका सुनिश्चत करना है।

■ 48 नई पंचायत समितियां व 1264 ग्राम पंचायतें

राज्य में 48 नई पंचायत समितियों व 1264 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में गठित केबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद इस सम्बन्ध में 16 नवम्बर, 2019 को अधिसूचना जारी की गई। प्रदेश में अब 11,152 ग्राम पंचायतें व 343 पंचायत समितियां हो गई हैं।

■ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

सांभर झील में पक्षियों की मौत के बाद राज्य सरकार ने 29 नवम्बर, 2019 को 20 सदस्यीय राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी) का गठन किया है। प्राधिकरण का अध्यक्ष वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई को बनाया गया है। इसमें वन पर्यावरण, राजस्व और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की भागीदारी होगी।

प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र:-प्रदेश के सभी नदी, नाले, तालाब, झील आदि प्राधिकरण के अधीन होंगे। आर्द्रभूमि क्षेत्र में खनन, निर्माण, डायवर्जन आदि प्राधिकरण की मंजूरी से ही होंगे।

■ राजस्थान कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसम्बर, 2019 को 'राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019' जारी की। यह नीति 31 मार्च, 2024 तक मान्य होगी तथा वर्ष 2021 में इसकी समीक्षा की जाएगी। इसका प्रमुख उद्देश्य समूह आधारित उत्पादन एवं कृषि प्रसंस्करण की अवधारणा को प्रोत्साहित करना, फार्म स्तर पर आधारभूत ढांचे का संवर्धन तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की मूल्य एवं आपूर्ति श्रृंखला में पूंजी निवेश को गति देना है। इसके साथ ही एक हजार करोड़ रुपए के 'किसान कल्याण कोष' का शुभारंभ भी किया गया।

■ राज्य सरकार के एक साल पूरा होने पर घोषणाएं

राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई घोषणाएं की। इनमें प्रमुख हैं-

निरोगी राजस्थान अभियान:- मुख्यमंत्री ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के सभागार में 18 दिसम्बर, 2019 को 'निरोगी राजस्थान' अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक महिला एवं एक पुरुष 'स्वास्थ्य मित्र' नियुक्त किया जाएगा, जो लोगों को बीमारियों से बचाव के बारे में जागरुक करेगा।

जनता क्लिनिक:- लोगों के घर के नजदीक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 'जनता क्लिनिक' की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसम्बर, 2019 को जयपुर के वाल्मीकि नगर में पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया। प्रदेश में पहले चरण में जयपुर में 12 तथा जोधपुर में 03 जनता क्लिनिक खोले जाएंगे।

जन आधार कार्ड:- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसम्बर, 2019 को पांच महिलाओं को जन आधार कार्ड प्रदान कर 'जन आधार कार्ड' का शुभारंभ किया। आमजन तक विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन आधार कार्ड योजना शुरू की गई है।

इंदिरा महिला शक्ति:- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसम्बर, 2019 को महिला सशक्तीकरण को समर्पित 'इंदिरा महिला शक्ति निधि' की योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके लिए राज्य में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से पांच वर्ष में एक करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा।

■ राजस्थान औद्योगिक विकास नीति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसम्बर, 2019 को नई 'राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019' को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत निम्न बिन्दुओं पर बल दिया जाएगा-

1. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लचीला बनाना, निजी भूमि-रीको द्वारा निवेश तथा रीको की भूमि-निजी निवेश मॉडल पर पीपीपी मोड पर औद्योगिक पार्कों का विकास।
2. एंकर इकाइयों को आकर्षक प्रोत्साहन एवं स्टार्टअप हेतु नई स्टार्टअप नीतियों का निर्माण
3. प्लग एंड प्ले सुविधाओं एवं बहुमंजिला कारखानों को बढ़ावा देना।
4. पिछले क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु रियायती दर पर बंजर भूमि का आवंटन।
5. पेट्रो केमिकल उद्योग के लिए तेल रिफाइनरी के पास औद्योगिक टाउनशिप विकसित करना।
6. एमएसएमई को गुणवत्ता प्रमाणन, रिसर्च एंड डवलपमेंट आदि में सहायता।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, कुटीर उद्योग, फुटकर व्यापारियों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष योजना का प्रावधान।
8. थ्रस्ट सेक्टर एवं पिछड़े व अति पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन।

■ राजस्थान सौर ऊर्जा नीति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसम्बर, 2019 को नई 'राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2019' को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत निम्न बिन्दुओं पर बल दिया जाएगा-

1. नई नीति में वर्ष 2024-25 तक 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 4 हजार मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. निजी क्षेत्र कृषि भूमि का उपयोग पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए बिना भू रूपान्तरण किया जा सकेगा।
3. नई नीति के तहत सौर एवं पवन ऊर्जा उपकरण निर्माताओं को स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट, 50 फीसदी की रियायती दर पर भूमि आवंटन, 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट, एसजीएसटी में 90 प्रतिशत तक निवेश अनुदान सहित कई प्रावधान किए गए हैं।

■ मरूगंधा परियोजना

जैसलमेर के पोकरण में 10 दिसम्बर, 2019 को अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने 'मरूगंधा परियोजना' का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य इको टूरिज्म के क्षेत्र में आजीविका संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना है।

■ देश का चौथा भालू अभयारण्य

राजस्थान में भालू अभयारण्य बनाया जाएगा। यह प्रदेश का पहला और देश का चौथा भालू अभयारण्य होगा। यह भालू अभयारण्य सिरोही जिले की माउंट आबू सेंक्चुअरी के 326.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और जालोर के सुंधा माता कंजरवेशन रिजर्व के 117.49 वर्ग किलोमीटर के जंगल को मिलाकर बनाया जाएगा। यह पूरा इलाका प्रदेश के तीनों टाइगर रिजर्व से अलग है।

नियुक्ति/निर्वाचन

■ महेश कुमार शर्मा

राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश कुमार शर्मा ने 5 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने 25 नवम्बर, 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

चर्चित व्यक्ति

■ जस्टिस प्रकाश टाटिया

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने 25 नवम्बर, 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें 11 मार्च, 2016 को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल मार्च, 2021 तक था।

■ एशियाई तीरंदाजी: रजत व प्रिया को पदक

जयपुर के रजत चौहान व प्रिया गुर्जर ने 22-28 नवम्बर, 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप में कम्पाउंड वर्ग की टीम स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया।

■ विश्व पैरा एथलेटिक्स : सुंदर को स्वर्ण पदक

दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में राजस्थान के एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 61.22 मीटर दूर तक भाला फेंककर शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

पुरस्कार

■ लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार

राजस्थान के लोक कला मर्मज्ञ डॉ. कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित 'लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार' गुजरात के हसमुख ब्रजलाल याज्ञिक को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 2.51 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे।

■ राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2019

'राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2019' का वितरण 14 दिसम्बर को जयपुर में आयोजित एक समारोह में किया गया। ऊर्जा संरक्षण के लिए सरकारी भवन की श्रेणी में उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्यालय भवन को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। स्टेशन श्रेणी में जोधुपर के स्टेशन को प्रथम व गांधी नगर जयपुर को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं, ऊर्जा संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य करने पर कोटा सुपर पावर थर्मल को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण का द्वितीय पुरस्कार मिला।

■ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व नरेगा में राज्य को 11 पुरस्कार

राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए 19 दिसम्बर, 2019 को 11 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

- राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य को आवास पूर्ण करने की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया।
- बांसवाड़ा की पंचायत समिति घाटोल को आवास पूर्ण करने की श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया।
- क्षेत्रीय स्तर पर योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के डूंगरपुर की ग्राम पंचायत रेटा, झूथरी की सरपंच सविता देवी को एवं हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत अजीतपुरा, भादरा के ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश सिंह को पुरस्कृत किया गया।
- राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना में जिला स्तर पर जियो टेगिंग मनरेगा इनिशिएटिव के लिए कोटा को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- ग्राम पंचायत स्तर पर जियो टेगिंग मनरेगा एनिशिएटिव एमएसई के तहत डूंगरपुर की सरा ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया।
- ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए जैसलमेर की हरनाव ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ आधारभूत ढांचा निर्माण व जल संग्रहण ढांचा निर्माण में वृद्धि के लिए भीलवाड़ा के आसीन्द ब्लॉक की मोतीपुर ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया।
- ग्रामीण विकास एवं पंचासती राज विभाग जोधपुर एवं उदयपुर स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को पुरस्कृत किया गया।
- राजस्थान को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बेहतर क्रियान्विति और सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की सड़कों के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2018-19 को बेस्ट परफॉरमेंस अवॉर्ड दिया गया।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने पर सरकारी नौकरी :-

राजस्थान अब नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान करेगा। राजस्थान यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य है।

पुष्कर मेला:-

पुष्कर मेले का आयोजन 8 (कार्तिक मास की एकादशी)-12 (कार्तिक पूर्णिमा) नवम्बर, 2019 तक किया गया।

बूंदी उत्सव :-

बूंदी उत्सव का शुभारंभ 15 नवम्बर, 2019 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने किया। पन्द्रह दिवसीय इस मेले का समापन 29 नवम्बर, 2019 को हुआ।

4 राजस्थान सुजस सार

(नवम्बर, 2019)

■ सीएम ने लिया रिफाइनरी के काम का जायजा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 नवम्बर को बाड़मेर के पचपदरा में एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम 'एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी' के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। परियोजना का करीब एक-चौथाई कार्य प्रगति पर है। यह रिफाइनरी नौ मिलियन टन क्षमता की होगी।

■ राजस्थान को बेस्ट वैडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड

राजस्थान को बेस्ट वैडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड प्रदान किया गया है। राजस्थान की ओर से यह अवॉर्ड पर्यटन विभाग के निदेशक एवं नागौर के परबतसर से विधायक ने ग्रहण किया।

■ निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद का गठन

प्रदेश के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने एवं निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद का गठन किया है। यह परिषद निर्यातकों का मार्गदर्शन करने के साथ ही विभिन्न औद्योगिक संगठनों, निर्यातकों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के बीच समन्वय कर निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी।

■ सुन्दर गुर्जर को स्वर्ण पदक

दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के पैरा एथलीट सुन्दर गुर्जर को लगातार दूसरी बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक मिला है।

■ स्वास्थ्य एवं पोषण सुधारों में धौलपुर अव्वल

नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र के सुधारों के पैरामीटर्स में धौलपुर जिले ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग ने 6 नवम्बर को देश के 112 जिलों की रैंकिंग जारी की है।

■ लर्निंग विद अर्निंग

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस परियोजना को प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय स्तर पर जानकीदेवी बजाज राजकीय कला महाविद्यालय कोटा द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा योग्य व जरूरतमंद विद्यार्थी अपने खर्चे को पूरा करने के लिए हर महीने उचित राशि अर्जित करने हेतु सक्षम बनाए जा रहे हैं।

■ लोककलाएं

- मलखम्ब - महाराष्ट्र
- नटुआ - पश्चिम बंगाल
- ढेड़िया - उत्तर प्रदेश
- सिरमोरी नाटी - हिमाचल प्रदेश
- केरवानुवेश - गुजरात
- डेरू - राजस्थान
- देखनी - गोवा
- पूजा कूनीथा - कर्नाटक

■ गवरी

गवरी लोकनाट्य भील समाज के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गवरी को एक तरह से ख्याल भी कहा जा सकता है। राजस्थानी भाषा में इस तरह चौराहों और चौपालों के पास गीत संगीत के साथ किए जाने वाले नाटक को ख्याल कहा जाता है। गवरी शब्द मां गौरी (पार्वती) से बना है। भील जनजाति का यह नृत्य आम तौर पर सावन और भाद्रपद में किया जाता है। इसमें मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे आम प्रचलन में राई नृत्य भी कहा जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेतीं। यह केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। गवरी में बूढ़िया और राई दो मुख्य पात्र होते हैं। बूढ़िया भगवान शिव और राई मां पार्वती को कहते हैं। यह नाट्य शिव-भस्मासुर की कथा से शुरू होता है। इसका मंचन रक्षाबंधन के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है जो सवा महीने तक चलता है। गवरी के समापन को गड़ावण कहा जाता है।

■ रम्मत

राजस्थान में रम्मत का इतिहास लगभग 900 साल पुराना है। वर्तमान में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पोकरण और नागौर में रम्मतें खेली जाती हैं। बीकानेर में होली के अवसर पर होलाष्टक लगने के साथ ही रम्मतों के मंचन का सिलसिला आरंभ हो जाता है जो होलिका दहन के एक दिन

पूर्व तक विद्यमान रहता है। रम्मत के मंच को अखाड़ा कहा जाता है। बीकानेर की प्रमुख रम्मतों में वीर रस प्रधान अमर सिंह राठौड़ की रम्मत का स्थान अग्रणी है। इसकी रचना विक्रम संवत 1911 में बीकानेर के मोतीलाल सेन ने इंदौर में की थी।

■ विभिन्न मेले

कोलायत का मेला - बीकानेर की कोलायत तहसील महर्षि कपिल की तपोभूमि है। यहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है।

पुष्कर मेला :- भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर अजमेर के पुष्कर में है। पुष्कर नाग पर्वत की तलहटी में पवित्र सरोवर के चारों ओर बसा है। यहां कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है।

लालजी कानजी मेला - चित्तौड़गढ़ के घोसुण्डा का लालजी कानजी मेला भी काफी प्रसिद्ध है।

■ मोलेला

राजस्थान में मृण शिल्प के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम 'मोलेला' है। यह गांव राजसमंद जिले में स्थित है जो राज्य के दक्षिण भाग मेवाड़ अंचल का हिस्सा है। यह गांव मृण मूर्तियों के लिए देशभर में विख्यात है। इस कला के कलाकार जमनाला प्रजापत को राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है।

■ फड़

राजस्थान में फड़ वाचन पश्चिम में प्रचुरता से देखा जा सकता है। फड़ सामान्यत: 4 फीट चौड़े और 16 से 40 मीटर लम्बे कपड़े पर बने होते हैं। इस कपड़े पर लाल, पीले, हरे आदि गहरे रंगों में गाथा की खंडों में चित्र बने होते हैं। यह विषय या गाथाएं लोक देवताओं के जीवन में आधारित होती हैं। फड़ को पृष्ठिभूमि में स्थापित कर भोपा-भोपी दृश्यों को छंद माध्यम से आमजन को सुनाते हैं। भोपा के हाथ में रावण हत्था होता है। फड़ बनाने के लिए भीलवाड़ा का जोशी परिवार ख्यातनाम है।

(दिसम्बर, 2019)

■ प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के मुताबिक अगले बजट में राज्य में एक सरकारी होम्योपैथी कॉलेज खोला जाएगा। वर्ष 2011 में प्रदेश में नि:शुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी।

■ उम्मीदों और उपलब्धियों का एक वर्ष

ज्ञान सम्पर्क पोर्टल योजना:- ज्ञान सम्पर्क पोर्टल योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। सरकार का मन्तव्य है कि जनभागीदारी से स्कूलों का कायाकल्प किया जाए।

राजस्थान शुभशक्ति योजना:- राजस्थान शुभशक्ति योजना के तहत निर्माण श्रमिकों की अविवाहित बेटियों को मदद दी जा रही है।

अपना खाता योजना:- किसानों को होने वाली परेशानियों और उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने अपना खाता योजना शुरू की है।

जल जीवन मिशन:- प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 23 परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय किया गया है। इससे 11 हजार गांव ढाणियों के 6 लाख घरों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

■ जन सूचना पोर्टल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 सितम्बर, 2019 को जयपुर में जन सूचना पोर्टल प्रदेश की जनता को समर्पित किया। प्रथम चरण में 13 विभागों की कुल जमा 23 प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

■ सीएसआर प्राधिकरण

प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए सीएसआर प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के परामर्शदात्री मंडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी तथा उद्योग मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। वहीं प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।

■ लोककल्याणकारी फैसलों से हुआ विकास

राज्य सरकार द्वारा एक साल के कार्यकाल में निम्न विकास कार्य किए गए हैं-

कृषक कल्याण :-

- 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया कुल 9 हजार 513 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ किए।
- दो लाख रुपए की सीमा तक के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ।

- दो लाख रुपए तक की सीमा का अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सेटलमेंट लाकर माफ करने का निर्णय।
- केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 6523 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित।
- एक हजार करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष गठित किया जा रहा है।
- आवारा पुशओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशाला स्थापित करने का निर्णय।
- लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2019 लागू। 75 साल से कम आयु के किसानों को 750 रुपए प्रतिमाह पेंशन। 75 और अधिक आयु के किसानों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में 1 फरवरी, 2019 से पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर का अंशदान।
- विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि की वसूली एवं प्रकरणों के निस्तारण की दृष्टि से देय ब्याज पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी हेतु 'ब्याज माफी योजना 2019'।

युवा कल्याण :-

- फरवरी, 2019 से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना लागू।
- मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना शुरू। एक लाख युवाओं को एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय।
- राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 07 नवम्बर, 2019 को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरू।
- 13 सितम्बर, 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण।
- जयपुर में महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना।

महिला सशक्तीकरण :-

- मेधावी छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना शुरू।
- बीपीएल परिवारों में होने वाले विवाह के वक्त आर्थिक सम्बल देने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू करने का निर्णय। इसके तहत पात्र कन्याओं को रुपए 21 हजार की सहायता दी जाएगी। इस योजना में आठवीं पास वयस्क बालिका ही पात्र होगी।

वृद्धजन कल्याण :-

- 46 लाख पेंशनर्स की वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपए वृद्धि।
- स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए मासिक की।

सैनिक कल्याण :-

- शहीद आश्रितों की सहायता राशि 50 लाख तक बढ़ाई।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा उनकी विध वाओं की पेंशन 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए की गई।

सामाजिक सुरक्षा :-

- अति पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं व सेवाओं में 5 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत तथा विशेष योग्यजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
- 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस राज्य में समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय। 9 अगस्त का ऐच्छिक अवकाश घोषित।
- 3 अक्टूबर, 2019 से राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 लागू।

ऊर्जा :-

- छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की छठी इकाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू।
- आगामी वर्षों में 4885 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा व 1426 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निविदा प्रारम्भ कर सौर ऊर्जा क्षमता को विकसित करने हेतु 1430 मेगावाट क्षमता का आवंटन।

पेयजल :-

- परम्परागत पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, नवीन स्रोतों का निर्माण व सघन वृक्षारोपण के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना का शुभारंभ 20 अगस्त, 2019 को किया गया।
- शहरी क्षेत्र में चालू मीटर वाले घरेलू कनेक्शन पर 15 किलोलीटर मासिक उपयोग तक वाटर चार्ज समाप्त।

शिक्षा :-

- डॉ.भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय पुनः खोले।
- पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन की घोषणा।
- आपकी बेटी योजना में कक्षा एक से आठ तक की बालिकाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 1100 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रतिवर्ष तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 1500 रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 2500 रुपए की गई।

चिकित्सा :-

- कैंसर, दिल, श्वास एवं गुर्दा रोग में उपचार की दवाओं सहित घोषित 104 नई दवाइयों में से 102 नई दवाइयां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की सूची में जोड़ी गईं।
- जनता क्लिनिक के माध्यम से गली-मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाएं।
- आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की 01 सितम्बर, 2019 से शुरुआत।
- खसरा-रूबेला अभियान के तहत प्रदेश में करीब 1.92 करोड़ बच्चों को टीके लगाए गए।

खाद्य सुरक्षा :-

- अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के 1 करोड़ 74 लाख पात्र लाभार्थियों को एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण किया जाना आरंभ।

उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यः-

- राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2019 प्रदेश में लागू।
- राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय। इसके तहत 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जोधपुर-पाली-मारवाड नोड के विकास के लिए 'विशेष निवेश क्षेत्र' की घोषणा।

लोककल्याणकारी कानूनः-

- मॉब लिंचिंग बिल विधानसभा में पारित। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बना।
- ई-सिगरेट और हुक्का बार पर प्रतिबंध।

स्वायत्तशासी संस्थाएंः-

- पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त।
- पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन कर 54 पंचायत समितियों तथा 1435 नवीन ग्राम पंचायतों का सृजन।
- जयपुर, जोधपुर व कोटा में दो-दो नगर निगम।

■ नेशनल वाटर मिशन अवॉर्ड

नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन अवार्ड समारोह में राजस्थान को दो श्रेणियों में राष्ट्रीय जल मिशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर मिशन के तहत देश में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए राष्ट्रीय वाटर मिशन अवार्डों में राजस्थान को दो श्रेणियों में प्रथम व द्वितीय पुरस्कार मिले।

■ कोंडेनास्ट ट्रेवलर इंडिया रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स

नई दिल्ली में 19 नवम्बर को आयोजित 9वें कोंडेनास्ट ट्रेवलर इंडिया रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2019 के समारोह में फेवरेट सिटी श्रेणी में राजस्थान पर्यटन ने दो अवॉर्ड जीते। फेवरेट सिटी इन इंडिया अवार्ड में जयपुर दूसरे स्थान पर रहा, वहीं उदयपुर ने फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया में अवॉर्ड जीता।

■ सुशासन में राजस्थान पहले स्थान पर

राजस्थान ने गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से यह अवॉर्ड ग्रहण किया।

5 रक्षा/विज्ञान प्रौद्योगिकी

■ समुद्र शक्ति-2019

भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास 'समुद्र शक्ति' का आयोजन 4-7 नवम्बर, 2019 को बंगाल की खाड़ी में किया गया। यह दोनों देशों की सेनाओं का ऐसा दूसरा अभ्यास है। इसमें आपसी तालमेल, युद्धाभ्यास, वायु रक्षा अभ्यास, फायरिंग ड्रिल, हेलिकॉप्टर संचालन एवं बोर्डिंग ऑपरेशन शामिल हैं। पहला अभ्यास इंडोनेशिया के सुराबाया के तट पर नवम्बर, 2018 में आयोजित किया गया था।

■ अग्नि-2 का रात्रिकालीन परीक्षण

भारत ने 16 नवम्बर, 2019 को ओडिशा के बालासोर स्थित डॉ. अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से अग्नि-2 मिसाइल का पहला रात्रिकालीन परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता सम्पन्न इस मिसाइल की मारक क्षमता 2,000 किमी है।

■ टाइगर ट्राइंफ

अमेरिका और भारतीय सेना के पहले संयुक्त त्रि-सेना मानवीय सहायता एवं आपदा अभ्यास 'टाइगर ट्राइंफ' का आयोजन आन्ध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में 12-21 नवम्बर, 2019 को किया गया। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता एवं आपदा अभियान में अंत: पारस्परिकता को बढ़ाना था। यह ऐसा दूसरा अवसर है जब भारत ने थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना सहित किसी दूसरे देश के साथ त्रि-सेवा युद्ध अभ्यास किया है। इससे पहले भारत ने रूस के साथ त्रि-सेवा युद्ध अभ्यास 'इंद्र' में हिस्सा लिया था।

■ दस्तालिक-2019

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहले संयुक्त फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास 'दस्तालिक-2019' का आयोजन 4-13 नवम्बर, 2019 को ताशकंद के निकट चिरचिक प्रशिक्षण क्षेत्र में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने में परस्पर सहायता को बढ़ाना था।

■ पृथ्वी-2

सेना की सामरिक बल कमान की ओर से ओडिशा के बालासोर से 20 नवम्बर, 2019 को परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित मिसाइल पृथ्वी-2 का रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का पहला रात्रिकालीन परीक्षण 27 जून, 2019 को किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम के लिए विकसित इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किमी है।

■ जायर-अल-बहर-2019

भारतीय नौसेना और कतर की शाही नौसेना के बीच 'जायर-अल-बहर: सागर की दहाड़' अभ्यास का आयोजन 17-21 नवम्बर, 2019 को कतर की राजधानी दोहा में किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, आतंकवाद, समुद्री डाकुओं से मुकाबला तथा समुद्री सुरक्षा रहा।

■ कार्टोसैट-3

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 27 नवम्बर, 2019 को आन्ध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा से कार्टोसैट सीरीज के उपग्रह कार्टोसैट-3 का प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण पीएसएलवी-सी-47 के जरिए किया गया। करीब 1625 किग्रा वजनी यह उपग्रह भारत का अब तक का सर्वाधिक रेजोल्यूशन वाला उपग्रह है, जो पृथ्वी पर नजर रखेगा। इसके शक्तिशाली कैमरे से अंतरिक्ष से जमीन पर एक फीट से भी कम ऊंचाई तक की तस्वीर ली जा सकेगी। कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, इस मिशन की अवधि पांच वर्ष है। कार्टोसैट-3 के साथ ही इसरो ने अमेरिका के 13 छोटे कमर्शियल सैटेलाइट्स भी प्रक्षेपित किए।

यह भी जानें:- कार्टोसैट सीरीज के पहले उपग्रह कार्टोसैट-1 का प्रक्षेपण 5 मई, 2005 को एवं कार्टोसैट-2 का प्रक्षेपण 10 जनवरी, 2017 को किया गया था।

■ वॉयजर-2 अंतरिक्ष यान

नासा का वॉयजर-2 अंतरिक्ष यान सौरमंडल की परिधि के बाहर इंटरस्टेलर क्षेत्र में पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है। वॉयजर-2 को 20 अगस्त, 1977 को लॉन्च किया गया था तथा इसके 16 दिन बाद 5 सितम्बर, 1977 को वॉयजर-1 लॉंच किया गया था। वॉयजर-2 ने 5 नवम्बर, 2018 को इंटरस्टेलर क्षेत्र में प्रवेश किया था। वॉयजर-2 से पहले नासा का ही वॉयजर-1 इस सीमा के पार पहुंचा था।

■ MK-45 नौसैनिक बंदूक

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 13 एमके- 45 नौसैनिक बंदूकें और संबंधित उपकरणों की बिक्री किए जाने के समझौते को मंजूरी दी है।

यह भी जानें:- MK-45 नौसैनिक बंदूक का इस्तेमाल तटों पर बमबारी, युद्धपोतों तथा युद्धक विमानों के खिलाफ किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 20 समुद्री मील से भी अधिक है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के बाद भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिन्हें अमेरिका ने इस बंदूक के नवीनतम संस्करण (MOD-4) बेचने का फैसला किया है।

■ कुफरी सह्याद्रि

केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, शिमला ने हाल ही में आलू की एक नई किस्म 'कुफरी सह्याद्रि' का विकास किया है। इस नई किस्म पर नेमोटोड्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा यह किस्म आलू की कुफरी ज्योति और कुफरी स्वर्ण किस्म का स्थान लेगी।

■ ग्लाइफोसेट

ग्लाइफोसेट एक प्रकार का खरपतवार नाशी है, जिसकी निर्माता जर्मनी की फार्मा कंपनी बायेर है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में शुरू किया गया था। यह एक प्रकार का गैर-चयनात्मक (Non-Selective) खरपतवारनाशी है जो कई पौधों को नष्ट कर देता है। यह पौधों में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के निर्माण को रोक देता है जो कि पौधों के विकास के लिए सहायक होते हैं।

चर्चा में क्यों:- नवम्बर, 2019 में कंपनी के इस उत्पाद के खिलाफ अमेरिका में हजारों लोगों ने मुकदमा दायर किया है। उनका तर्क है कि यह उत्पाद कैंसर का कारक है।

भारत की स्थिति :- भारत में इसका प्रयोग पिछले दो दशकों में काफी बढ़ा है। पहले इसका प्रयोग सिर्फ असम तथा बंगाल के चाय बागानों में किया जाता था, लेकिन अब इसका सर्वाधिक प्रयोग महाराष्ट्र में गन्ना, मक्का तथा फलों जैसे-अंगूर, केला, आम व संतरे को उगाने में किया जाता है। भारत में ग्लाइफोसेट का प्रयोग विशेषकर राउंडअप, ग्लाईसेल तथा ब्रेक नामक खरपतवारनाशी दवाओं में होता है।

■ मित्र शक्ति-2019

'मित्र शक्ति' भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। 'मित्र शक्ति-2019' का आयोजन 01-14 दिसम्बर, 2019 को महाराष्ट्र के पुणे स्थित औध सैन्य स्टेशन पर किया गया। इस अभ्यास का आयोजन वर्ष 2012 से किया जा रहा है।

उद्देश्य:- इस अभ्यास का उद्दूश्य भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों का निर्माण और संवर्द्धन करना है। इसके अलावा संयक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी और ग्रामीण परिवेश में जवाबी कार्रवाई तथा आतंकी कार्रवाईयों के मुकाबले के लिए उप इकाई स्तर के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।

■ सूर्यकिरण-2019

'सूर्यकिरण' भारत और नेपाल की सेना का संयुक्त वार्षिक अभ्यास है। 'सूर्यकिरण-2019' का आयोजन 03-16 दिसम्बर को नेपाल के रूपंदेही जिले में किया गया। इस दौरान जंगली व पहाड़ी क्षेत्रों में विद्रोही गतिविधियों से निपटने व आंतकवाद विरोधी कार्यवाहियों से सम्बन्धित अभ्यास किए गए। इससे पहले वर्ष 2018 में उत्तराखंड में यह अभ्यास आयोजित किया गया था।

■ हैंड इन हैंड-2019

'हैंड इन हैंड' भारत और चीन की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है। 'हैंड इन हैंड-2019' का आयोजन 7-20 दिसम्बर, 2019 को मेघालय के उमरोई में किया गया। इससे पहले यह अभ्यास वर्ष 2018 में चीन के चेंगदू में आयोजित किया

■ इन्द्र-2019

'इन्द्र' भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाला तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। 'इन्द्र-2019' का आयोजन 10-19 दिसम्बर, 2019 को भारत के बबीना, पुणे व गोवा में किया गया। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी।

उद्देश्य:- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक कौशल, अनुभव व सैन्य तकनीक को साझा करना है।

■ नाविक

अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के NAVIC उपग्रह को 'संबद्ध नौवहन उपग्रह प्रणाली' के रूप में यूरोपीय संघ के गैलीलियो और जापान के 'QZSS' के साथ नामित करने की सहमति दी है।

यह भी जानें :- नाविक (Navigation in Indian Constellation) आठ उपग्रहों की क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह आधारित स्वदेशी प्रणाली है जो अमेरिका के GPS की तरह कार्य करती है। इसके माध्यम से स्थानीय स्थितियां, स्थान आधारित सेवा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर 1,500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है।

■ अग्नि-3 का रात्रिकालीन परीक्षण

परमाणु क्षमता से लैस सतह-से-सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का 30 नवम्बर, 2019 को पहली बार रात में सफल परीक्षण हुआ। ओडिशा के बालासोर तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से यह परीक्षण किया गया। अग्नि-3 जो पहले से ही सेना का हिस्सा है।

यह भी जानें:- अग्नि-3 मिसाइल 3500 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। इसका वजन करीब 50 टन, लंबाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर है। यह डेढ़ टन तक परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है।

■ रीसेट-2BR1

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान-इसरो (Indian Space Research Organisation-ISRO) ने 11 दिसम्बर, 2019 को PSLV-C48 रॉकेट की मदद से रीसैट-2BR1 (RISAT-2BR1) नामक सैटेलाइट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। रीसैट-2BR1 के अलावा 9 अन्य वाणिज्यिक सैटेलाइटों को भी निर्धारित कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया जो कि इजराइल, जापान, अमेरिका तथा इटली के थे। इन सैटेलाइटों को इसरो के वाणिज्यिक निकाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अधीन प्रबंधित किया गया था।

यह भी जानें:- रीसैट-2BR1 एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है तथा इसका वजन 628 किलोग्राम है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट मिशन की अवधि पांच वर्ष है।

पीएसएलवी की 50वीं उड़ान :- यह PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV) रॉकेट द्वारा किया गया 50वां प्रक्षेपण था। PSLV रॉकेट के 50वें लॉन्च के मौके पर इसरो द्वारा " PSLV/50" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

■ मिग-27

लड़ाकू विमान मिग-27 दिसम्बर, 2019 में भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गया है। भारतीय वायु सेना के बेड़े में 1985 में शामिल किया गया यह अत्यंत सक्षम लड़ाकू विमान जमीनी हमले की क्षमता का आधार रहा है। वायु सेना के सभी प्रमुख ऑपरेशन्स में भाग लेने के साथ मिग-27 ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी।

■ अभ्यास अपहरण

भारतीय नौसेना ने 18-19 दिसम्बर, 2019 को कोच्चि बंदरगाह पर एंटी हाइजैकिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया। 'अपहरण' नामक इस अभ्यास का उद्देश्य प्रतिक्रिया तंत्र/तैयारी को कारगर बनाना था, ताकि देश विरोधी तत्त्वों द्वारा किसी व्यापारी जहाज को हाईजैक करने या किसी अपहृत जहाज को जबरन प्रवेश कराने के प्रयासों को विफल किया जा सके।

■ ब्रह्मोस मिसाइल

भारत ने दिसम्बर, 2019 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नवीनतम संस्करण के दो सफल परीक्षण (भूमि और वायु से) किए। इसका उद्देश्य ब्रह्मोस मिसाइल को नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है।

यह भी जानें:- ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ने तैयार किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक क्रूज मिसाइल है किंतु जब इसकी गति 2.8 मैक होती है अर्थात् इसकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से भी तीन गुना अधिक होती है, तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाती है। इसकी वास्तविक रेंज 290 किलोमीटर है परंतु लड़ाकू विमान से दागे जाने पर यह लगभग 400 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, हवा और जमीन से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पहले संस्करण को वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

■ पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा दिसम्बर, 2019 में ओडिशा के चांदीपुर तट के निकट स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया।

यह भी जानें:- पिनाका आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता पूरी सटीकता के साथ 75 किलोमीटर है। पिनाका के उन्नत संस्करण में नौसंचालन, नियंत्रण और दिशा-प्रणाली जोड़ी गई हैं, ताकि उसकी सटीकता और रेंज में वृद्धि हो सके। इसकी रेंज की ट्रैकिंग, दूरमापी, रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग प्रणाली से की जाती है।

■ अपाचे हेलीकॉप्टर

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर (AH-64E Apache Helicopters) के लिए दिसम्बर, 2019 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

यह भी जानें :- भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्ष 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए समझौता हुआ था। इसमें से सितम्बर, 2019 में 8 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिए गए हैं। इसकी आखिरी खेप मार्च, 2020 में मिलेगी। यह सेना में पहले से शामिल रूसी हेलीकॉप्टर डप-35 की जगह लेगा।

Samyak
An Institute For Civil Services

BATCH STARTS

RAS
FOUNDATION
Hindi Med. @ 08 Am - 1 Pm
English Med. @ 04 Pm - 07 Pm

IAS
FOUNDATION
Hindi Med. @ 08 Am - 12 Pm
English Med. @ 04 Pm - 07 Pm

IAS & RAS
3 YEARS INTEGRATED COURSE
Course Along With Graduation
@ 04 Pm - 07 Pm

ONE YEAR COMPREHENSIVE TEST SERIES PROGRAM
*For RAS PRE CUM MAINS
TEST SERIES, WORKSHOP & DISCUSSION
(TOTAL 54 TEST) ON Every Sunday @ 10 am. to 01 pm.
In Hindi & English Medium (Online & Offline)

6 आर्थिक घटनाक्रम

■ फॉर्च्यून की 'बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर' सूची

बिजनेस पत्रिका 'फॉर्च्यून' की ओर से नवम्बर, 2019 में जारी की गई टॉप-20 बिजनेस लीडर्स की सूची में भारतीय मूल के तीन लोगों ने जगह बनाई है। 'बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर-2019' शीर्षक से जारी इस सूची में शामिल भारतवंशियों में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला (प्रथम), मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा (8वां स्थान) व अरिस्टा की प्रमुख जयश्री उल्लाल (18वां स्थान) शामिल हैं।

शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता बिजनेस पर्सन:-

स्थान	व्यक्ति
1	सत्य नडेला (माइक्रोसॉफ्ट)
2	एलिजाबेथ गेन्स (फोर्ट्सक्यू मेटल)
3	ब्रायन निकॉल (चिपोटले मेक्सिकन ग्रिल)

■ आइवडैश एवं अतिथि

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी की बेहतर निगरानी और अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करने में तेजी लाने के उद्देश्य से 4 नवम्बर, 2019 को आइसडैश (ICEDASH) एवं अतिथि (ATITHI) का शुभारंभ किया।

ICEDASH:-यह एप केंन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत भारतीय बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर आयातित वस्तुओं के कस्टम क्लियरेंस को गति प्रदान करने तथा उसकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है।

ATITHI:-यह एप भारत में आने वाले अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया।

■ विश्व का प्रथम सीएनजी पोर्ट टर्मिनल

गुजरात के भावनगर में विश्व के पहली कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) पोर्ट टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजक्ट को 10 नवम्बर, 2019 को मंजूरी प्रदान की है। इसकी वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 60 लाख मीट्रिक टन है।

■ कृषि वायदा सूचकांक

'नेशनल एक्सचेंज कमोडिटी एवं डेरेवेटिव्स एक्सचेंस' (NCDEX) ने 13 नवम्बर, 2019 को रिटर्न आधारित कृषि वायदा सूचकांक 'एग्रीडेक्स' लॉन्च किया। यह NCDEX के प्लेटफार्म पर 10 सबसे तरल जिंसों के प्रदर्शन पर नजर रखेगा तथा इसे प्रदर्शित करेगा।

■ 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा

केन्द्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में एक साल की बढ़ोतरी की है। अब आयोग को वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग को कर वसूली और कुछ अन्य संसाधनों का बंटवारा केन्द्र व राज्यों के बीच किस प्रकार किया जाए, इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

यह भी जानें:- संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवम्बर, 2017 को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। इसका गठन अगले पांच वर्ष (1 अप्रेल, 2020 से 31 मार्च, 2025) के लिए वित्तीय मामलों तथा कर निर्धारण के लिए किया गया।

आयोग ने सौंपी वर्ष 2020-21 के लिए रिपोर्ट:- 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट 5 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को तथा 6 दिसम्बर, 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी।

■ ग्रामीण एवं कृषि वित्त पर छठवीं विश्व कांग्रेस

ग्रामीण एवं कृषि वित्त पर छठवीं विश्व कांग्रेस का आयोजन 12-13 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में किया गया। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन, नाबार्ड और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन किया गया। इस कांग्रेस का उद्देश्य ग्रामीण एवं कृषि वित्त के सभी हितधारकों को एकत्रित करना है। यह व्यापारिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने तथा अपने उत्पादों व सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है।

■ कॉरपोरेशन व आंध्र का यूनियन बैंक में विलय

वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेशन बैंक व आंध्र बैंक का यूनियन बैंक में विलय किए जाने को लेकर नवम्बर, 2019 में अपनी सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की है। विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है।

■ भारत-यूरोप बिजनेस फोरम

केन्द्रीय विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से 5वें 'भारत-यूरोप 29 बिजनेस फोरम' का आयोजन 20-21 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में किया गया। फोरम में 29 यूरोपीय देशों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें स्मार्ट सिटीज, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल तथा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी आदि पर चर्चा की गई।

■ फॉर्चून इंडिया-500 सूची में रिलायंस शीर्ष पर

दिसम्बर, 2019 में जारी फॉर्चून इंडिया-500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2018-19 में मुकेश अम्बानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का कारोबार 5.81 लाख करोड़ रुपए का रहा। उल्लेखनीय है कि इस सूची में गत दस वर्षों से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शीर्ष स्थान पर थी।

सूची में शीर्ष 5 स्थान प्राप्तकर्ता :-

रैंक	कंपनी
1	रिलायंस इंडस्ट्रीज
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
3	ओएनजीसी
4	भारतीय स्टेट बैंक
5	टाटा मोटर्स

■ एडीबी ने घटाई भारत की विकास दर

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) ने दिसम्बर, 2019 में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 फीसदी से घटाकर 5.1 फीसदी कर दिया है। ADB ने वर्ष 2019-20 के लिए सितम्बर में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 फीसदी और उसके बाद 7.2 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया था।

■ सीएफए फ्रेंक का नाम अब 'ईको'

पश्चिम अफ्रीका के आठ देशों (माली, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्किना फोसा, गिनी बिसाऊ तथा आइवरी कोस्ट) ने 21 दिसम्बर, 2019 को अपनी साझा मुद्रा 'सीएफए फ्रेंक' का नाम बदलकर 'ईको' रखने का निर्णय किया है। ये देश गत 74 साल से सीएफए फ्रेंक का उपयोग कर रहे थे और फ्रांस किसी भी वित्तीय संकट के गारंटर के रूप में काम करता था।

■ विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर के पार

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार पहली बार 450 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 451.7 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया जो अब तक का अधिकतम आँकड़ा है। उल्लेखनीय है की चालू वित्त वर्ष में गत वर्ष की तुलना में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 38.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है।

विदेशी मुद्रा भंडार:- किसी देश में समय विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भण्डार कहते हैं। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित चार तत्त्व शामिल होते हैं:-

1. विदेशी परिसंपत्तियां (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
2. स्वर्ण भंडार
3. IMF के पास रिजर्व कोष
4. विशेष आहरण अधिकार

7 खेल जगत्

क्रिकेट

■ भारत-बांग्लादेश सीरीज

3-26 नवम्बर, 2019 में भारत के दौरे पर रही बांग्लादेश की टीम ने यहां तीन टी-20 व दो टेस्ट सीरीज खेलीं।

टेस्ट सीरीज :- भारत ने पहला टेस्ट पारी व 130 रन तथा दूसरा टेस्ट पारी व 46 रन से जीता। इसके साथ ही भारत लगातार चार मैच पारी से जीतने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली व बांग्लादेश की टीम के कप्तान मोमिनुल हक थे। इशांत शर्मा को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' घोषित किया गया। 22-24 नवम्बर को कोलकाता के ईडन गार्डन पर खेला गया सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच डे-नाइट था। यह भारत का पहला डे-नाइट टेस्ट मैच था।

टी-20 सीरीज :- 3-10 नवम्बर के दौरान खेली गई टी-20 सीरीज भारत ने 2-1 से जीती। तीसरे व अंतिम मैच में भारत के दीपक चाहर ने हैट्रिक बनाई। टी-20 मैच में हैट्रिक बनाने वाले वे भारत के पहले गेंदबाज हैं। दीपक चाहर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड:- रोहित शर्मा टी-20 में 2,500 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

■ भारतीय महिला टीम का वेस्टइंडीज दौरा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम नवम्बर, 2019 में वेस्टइंडीज के दौरे पर रही। यहां उसने मेजबान टीम के साथ तीन वनडे व पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेली।

वन डे सीरीज:- 1-6 नवम्बर के बीच तीन वन डे मैचों की सीरीज खेली गई। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया। भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज व वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर थीं। वेस्टइंडीज की स्टेफनी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

टी-20 सीरीज :- 9-20 नवम्बर के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली गई। भारत ने वेस्टइंडीज को 5-0 से हराया। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

शेफाली का रिकॉर्ड:- शेफाली वर्मा अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्द्धशतक लगाने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था।

■ भारत-वेस्टइंडीज सीरीज

6-22 दिसम्बर, 2019 को भारत दौरे पर रही वेस्टइंडीज की टीम ने यहां तीन टी-20 मैच व तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली।

टी-20 सीरीज:- 6-11 दिसम्बर को खेली गई तीन मैचों की टी-20 सीरीज भारत ने 2-1 से जीती। कप्तान विराट कोहली को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट घोषित किया गया।

वन-डे सीरीज :- 15-22 दिसम्बर को खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज भारत ने 2-1 से जीती। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

रोहित का रिकॉर्ड:- कटक के बाराबती स्टेडियम पर खेले गए मैच में रोहित शर्मा ने 63 रन की पारी खेलकर इस वर्ष कुल 2442 रन बनाए। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने का श्रीलंका के सनथ जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।

कुलदीप का रिकॉर्ड :- स्पिनर कुलदीप यादव वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वन डे में हैट्रिक लेकर दो अन्तराष्ट्रीय हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2017 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक ली थी।

■ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी

कर्नाटक ने 1 दिसम्बर, 2019 को हुए फाइनल मैच में तमिलनाडु को हराकर सैयर मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। भारतीय घरेलू क्रिकेट में यह पहला मौका था जब विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में खेलने वाली दोनों टीमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी आमने-सामने थीं।

टेनिस

■ फेड कप : फ्रांस तीसरी बार विजेता

टेनिस में महिला टीम का प्रतिष्ठित फेड कप टूर्नामेंट (57वां) फ्रांस ने जीता। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 9-10 नवम्बर, 2019 को सम्पन्न हुए मुकाबले में फ्रांस ने सात बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को 2-3 से हराया। फ्रांस ने तीसरी बार यह खिताब जीता है।

■ डेविस कप : स्पेन छठी बार विजेता

टेनिस में पुरुष टीम का प्रतिष्ठित डेवस कप (108वां) टूर्नामेंट स्पेन ने जीता। 24 नवम्बर, 2019 को स्पेन के मैड्रिड में हुए फाइनल मैच में स्पेन ने कनाडा को 2-0 से हराते हुए छठी बार इस खिताब पर कब्जा जमाया।

हॉकी

■ भारत को विश्व कप की मेजबानी

वर्ष 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्वकप की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 8 नवम्बर, 2019 को इसकी घोषणा की। इससे पहले भारत वर्ष 1982, 2010, 2018 में हॉकी विश्वकप की मेजबानी कर चुका है।

महिला हॉकी विश्वकप:- महिला हॉकी विश्वकप 2022 की मेजबानी स्पेन और नीदरलैंड्स को संयुक्त रूप से सौंपी गई है।

शतरंज

■ वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप-2019

भारत की युवा महिला ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी ने वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप-2019 का खिताब जीता है। 28 दिसम्बर, 2019 को मॉस्को में सम्पन्न प्रतियोगिता में हंपी ने टाईब्रेकर की सीरीज में चीन की लेई तिंगजी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। हंपी देश की पहली महिला वर्ल्ड चैम्पियन हैं।

वहीं, पुरुषों में नार्वे के मैग्नस कार्लसन ने तीसरी बार वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप का खिताब जीता।

फुटबॉल

■ फीफा अंडर 17 विश्व कप : ब्राजील विजेता

फीफा अंडर 17 विश्व कप (18वां) का आयोजन 26 अक्टूबर-17 नवम्बर, 2019 को ब्राजील में किया गया। प्रतियोगिता में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। 17 नवम्बर को खेले गए फाइनल मैच में ब्राजील ने मैक्सिको को 2-1 से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार ब्राजील के गैबरील बेरॉन को, गोल्डन बूट पुरस्कार नीदरलैंड्स के सोंटेज हेन्सन को, गोल्डन ग्लव पुरस्कार ब्राजील के माथियस डोनेली को तथा फीफा फेयर प्ले अवॉर्ड इक्वाडोर को दिया गया।

निशानेबाजी

■ एशियन निशानेबाजी चैम्पियनशिप

14वीं एशियन निशानेबाजी चैम्पियनशिप का आयोजन 5-13 नवम्बर, 2019 को कतर के दोहा में किया गया। यह वर्ष 2020 में जापान के टोक्यो में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए एशियाई क्वालीफाइंग टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट में 45 पदकों के साथ चीन शीर्ष पर रहा, वहीं भारत को 26 पदकों (5 स्वर्ण, 10 रजत व 11 कांस्य) के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने इस प्रतियोगिता में छह ओलम्पिक कोटा हासिल किए।

■ ISSF विश्वकप-2019

चीन के पुतियान में 17-23 नवम्बर, 2019 को ISSF विश्वकप का आयोजन किया गया।

भारत को पदक :- भारत की मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मी. एयर पिस्टल में स्वर्ण, इलावेनिल वलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण और दिव्यांश पवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता।

बैडमिंटन

■ BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स

वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ के वर्ष 2019 के अंतिम टूर्नामेंट 'वर्ल्ड टूर फाइनल्स' का आयोजन 11-15 दिसम्बर को चीन के गुआंगझु में किया गया।

ये रहे विजेता-

- **पुरुष एकल विजेता** - केंटो मोमोता (जापान)
  उपविजेता -एंथोनी सिनीसुका गिंटिंग (इंडोनेशिया)
- **महिला एकल विजेता** - चेन यूफेई (चीन)
  उपविजेता- ताइ त्जु यिंग (चीन)
- **पुरुष युगल** विजेता - मोहम्मद अहसान (इंडोनेशिया) व हेन्द्रा सेतियावान (इंडोनेशिया)
  उपविजेता- हिरोयुकी एंडो (जापान) व युता बतानबे (जापान)

- **महिला युगल विजेता**- चेन किंगचेन (चीन) व जिया यीफान (चीन)
  उपविजेता- मायु मात्सुमोतो (जापान) व वकाना नागाहरा (जापान)
- **मिश्रित युगल - विजेता** - झेंग सीवेई (चीन) व हुआंग याकियोंग (चीन)
  उपविजेता- वांग यिल्यु (चीन) व हुआंग डोंगपिंग (चीन)

बॉक्सिंग

■ एशियन यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप

मंगालिया के उलानबटार में नवम्बर, 2019 में एशियन यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 15 पदकों के साथ कजाखस्तान ने तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, वहीं भारत 12 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत के लिए चारों स्वर्ण पदक महिला मुक्केबाजों ने जीते।

भारत के पदक विजेता:-

- **स्वर्ण**- नाओरेम चानू, विनका, सनामाचा चानू, पूनम व सुषमा।
- **रजत** - सेलेय रॉय, अंकित नरवाल।
- **कांस्य** - सत्येन्द्र सिंह, अमन, अरुंधती चौधरी, कोमलप्रीत व जैसमीन।

एथलेटिक्स

■ विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप-2019

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन 7-15 नवम्बर, 2019 को दुबई में किया गया। प्रतियोगिता में 118 देशों ने हिस्सा लिया। 59 पदक जीतकर चीन ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं भारत कुल 9 पदक (2 स्वर्ण, 2 रजत व 5 कांस्य) के साथ 24वें स्थान पर रहा। साथ ही भारत ने टोक्यो ओलम्पिक-2020 के लिए 13 कोटा भी हासिल किया।

तीरंदाजी

■ एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप-2019

21वीं एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप का आयोजन 22-28 नवम्बर, 2019 को थाइलैंड के बैंकॉक में किया गया। 13 पदकों के साथ दक्षिण कोरिया पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, वहीं भारत ने 7 पदक (1 स्वर्ण, 2 रजत व 4 कांस्य) जीते।

भारत के पदक विजेता :-

- **स्वर्ण** - मिश्रित कंपाउंड टीम (अभिषेक वर्मा व ज्योति सुरेखा)।
- **रजत** - पुरुष कंपाउंड टीम (मोहन भारद्वाज, रजत चौहार व अभिषेक वर्मा) तथा महिला कंपाउंड टीम (प्रिया गुर्जर, मुस्कान किरार व ज्योति सुरेखा)।
- **कांस्य** - अतानु दास (पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्द्धा), पुरुष रिकर्व टीम (अतानु दास, तरुणदीप राय व जयंत तालुकदार), महिला रिकर्व टीम (अंकिता भक्त, दीपिका कुमारी व बोम्बायला देवी)।

फार्मूला वन रेस

■ वर्ल्ड चैम्पियनशिप

मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक लुइस हैमिल्टन ने 3 नवम्बर, 2019 में छठी बार फार्मूला वन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब जीता। वे अब सात बार के विश्व चैम्पियन माइकल शूमाकर से एक खिताब पीछे हैं। इस वर्ष कुल 21 फार्मूला वन रेसों का कार्यक्रम था। 3 नवम्बर, 2019 को 19 रेसों के पश्चात ही हैमिल्टन के अंक इतने हो गए कि शेष दो रेसों के परिणाम उनके इस स्थान को प्रभावित नहीं कर सकते थे, जिसके चलते उनका वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब सुनिश्चित हो गया।

अन्य

■ 13वें दक्षिण एशियाई खेल

13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 01-10 दिसम्बर, 2019 को नेपाल में किया गया। खेलों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश व श्रीलंका के 2715 खिलाड़ियों ने 26 खेलों में हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारत के ध्वजवाहक तेजिंदर सिंह थे। इन खेलों के लोगों के रूप में एक उड़ते हुए कबूतर को दर्शाया गया है।

पदक तालिका:-

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
भारत	173	93	45	311
नेपाल	51	60	95	206
श्रीलंका	40	83	128	251
पाकिस्तान	32	41	59	132
बांग्लादेश	19	32	87	138
मालदीव	01	00	04	05
भूटान	00	07	13	20

■ लक्ष्य सेन ने जीता खिताब

भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने दिसम्बर, 2019 में 'बांग्लादेश अन्तरराष्ट्रीय चैलेंजर' का खिताब जीता। यह उनका सत्र का 5वां खिताब है। ढाका में खेले गए फाइनल मैच में उन्होंने मलेशिया के लेआंग जुन हाओ को हराया।

■ अन्तरराष्ट्रीय कबड्डी विश्वकप

पंजाब में खेले गए अन्तरराष्ट्रीय कबड्डी विश्वकप में मेजबान भारत ने कनाडा को 64-19 से हरा खिताब जीता।

■ मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक

कतर में आयोजित छठवें कतर भारोत्तोलन इंटरनेशनल कप में भारत की मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 49 किग्रा भारवर्ग में 194 किग्रा वजन उठाकर पदक हासिल किया।

8 पत्रिकाओं से... योजना/ कुरूक्षेत्र सार

योजना

उदीयमान भारत (सितम्बर)

■ 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हेतु कदम

हाल ही में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने 2024 तक भारत के लिए पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की घोषणा की। आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2020 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7 प्रतिशत निर्धारित की गई है जो पिछले साल 6.8 प्रतिशत से अधिक थी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम:- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के आर्थिक उत्पादन में 30 प्रतिशत का योगदान देने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी 30 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं।

कृषि क्षेत्र पर जोर:- भारत की 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि कार्यों में संलग्न है। विश्वभर में ढुलाई किए जाने वाली वस्तुओं का 60 से 80 प्रतिशत हिस्सा कृषि पदार्थों का होता है। किसानों को उत्पाद के बेहतर दाम दिलाने के लिए ई-नाम शुरू किया गया है।

सेवा क्षेत्र पर जोर:- सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद में 56.5 प्रतिशत का योगदान देती हैं, लेकिन इनसे रोजगार के सिर्फ 30 प्रतिशत अवसर उत्पन्न होते हैं।

डिजिटल इंडिया:- डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत 1 जुलाई, 2015 को की गई थी। डिजिटल उपभोक्ताओं की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में दूसरे नम्बर पर है।

■ जल संरक्षण-एक राष्ट्रीय आंदोलन

भारत में वैश्विक आबादी का लगभग छठा हिस्सा और पशुधन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र दुनिया का मात्र 2.4 प्रतिशत है। धरती 70 प्रतिशत जल से आच्छादित है, किन्तु पृथ्वी पर ताजा जल केवल 2.5 प्रतिशत है। दुनिया के ताजा जल संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा भारत में है। मीठे पानी का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा आसानी से झील व नदियों में उपलब्ध है। आनुपातिक रूप से अकेले कृषि क्षेत्र में मानव द्वारा ताजे जल का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा काम में लाया जा रहा है।

2014-19 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने गंगा के कायाकल्प (अविरल और निर्मल धारा) के लिए 'नमामि गंगे' को लागू किया।

■ शासन प्रणाली में सुधार

नीति आयोग ने 'नया भारत@75 के लिए रणनीति' दस्तावेज जारी किया है। इसमें कुल 41 अध्यायों में से 7 में सिर्फ सरकार संचालन की प्रणाली पर फोकस किया गया है।

सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद:- 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और इसके बाद से सहयोगात्मक संघवाद के जरिए केन्द्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने पर नए सिरे से जोर दिया गया। पारदर्शी रैंकिंग के जरिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य सूचकांक, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, एसडीजी सूचकांक और संभावनाशील जिलों का प्रदर्शन शामिल है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और आधार का उपयोग:- कुल 55 मंत्रालयों से जुड़ी 439 योजनाएं अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दायरे में आ चुकी हैं। साथ ही आज देश में 124 करोड़ लोगों के पास आधार नम्बर है।

परिणाम आधारित निगरानी:- केन्द्रीय बजट 2017-18 में परिणाम आधारित बजट की शुरुआत की गई। इसमें परिणामों पर ध्यान केन्द्रित कर लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है।

ई-शासन प्रणाली:- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू किया गया है। इसमें विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम तीन प्रमुख उद्देश्यों पर केन्द्रित है-डिजिटल आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण उपयोगिता, मांग आधारित शासन व्यवस्था और सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

■ ऊर्जा क्षेत्र से सामाजिक-आर्थिक विकास

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य-7 साफ-सुथरी ऊर्जा की उपलब्धता से जुड़ा है। भारत ऊर्जा की खपत करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में ऊर्जा की मांग 5 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रही है। साल 2040 तक यह मांग दोगुनी हो जाएगी।

सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 से अनुकूल नीति बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया है। एनडीए सरकार ने वर्ष 2017 में 'सौभाग्य' योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य सभी घरों तक बिजली पहुंचाना था। साल 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करते हुए भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है।

■ जरूरी है कौशल

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में जरूरी कौशल से लैस श्रम की आवश्यकता होगी। देश में आधी आबादी 25 साल से कम की है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण की मानें तो अगले दो दशकों में भारत की आबादी में तेज गिरावट का दौर आएगा। इसका मतलब यह भी है कि पूरे देश को 'जनांकिक लाभ' के दौर का फायदा मिलेगा और कुछ हिस्से में 2030 तक समाज में बुजुर्गों की बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। देश में आगामी दशक में कामकाजी आयु समूह के दायरे में 97 लाख लोग होंगे और 2030 इसमें सालाना 42 लाख की बढ़ोतरी होगी।

वित्त वर्ष 2009 में जब राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बनाई गई तो इस तरह के प्रशिक्षण के लिए शुरुआती कदम उठाए गए। इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास फंड की स्थापना की गई। वित्त वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की स्थापना हुई। नवम्बर, 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 तैयार की और इसके तहत कौशल विकास अभियान शुरू किया।

स्किल इंडिया (कौशल भारत) अभियान 2015 में शुरू किया गया। इससे जुड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मकसद उद्योगों सम्बन्धी कौशल के प्रशिक्षण के लिए युवाओं को एकत्र करना और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पहला संस्करण 2015 में शुरू किया गया और इसके तहत साल 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की बात है। स्किल इंडिया के तहत 3 करोड़ से भी ज्यादा और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

कौशल विकास केन्द्रः- साल 2015 से जून, 2019 तक 901 कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्राथमिक प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2016 में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना की शुरुआत की गई। जून 2019 तक इस योजना के तहत 11. 87 लाख उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ।

संकल्प अभियानः- वर्ष 2017 में शुरू किए गए 'संकल्प अभियान' का मकसद कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों के बीच सम्मिलन कायम करना, कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता बेहतर बनाना और उद्योग केन्द्रित व मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण क्षमता तैयार करना है।

स्ट्राइवः- वर्ष 2017 में 'स्ट्राइव' योजना शुरू की गई। इसका मकसद उद्योग समूहों के जरिए जागरूकता प्रदान करना और आईटीआई की प्रदाता गुणवत्ता का एकीकरण करना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगमः- इसने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए निजी क्षेत्र से जुड़ी 235 साझीदारी वाली इकाइयों को जोड़ा है और हर इकाई को 10 साल से भी ज्यादा की अवधि में कम से कम 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इसके लिए 38 कौशल परिषद बनाई गई हैं।

■ स्वास्थ्य सेवाओं की कायापलट

- वर्ष 2002 के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी घटनाएंः-
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2002
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - 2005
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना - 2008
- जन औषधि योजना - 2008
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - 2009
- खास तबके की आबादी के लिए राज्य केन्द्रित साजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं - 2008-17
- नदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम - 2010
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - 2013
- स्वच्छ भारत मिशन - 2014
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति - 2014
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम - 2017
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2017
- आयुष्मान भारत कार्यक्रम-प्रधानंत्री जनआरोग्य योजना -2018

■ अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचा

प्रधानमंत्री आवास योजना:- सरकार ने '2022 तक सबके लिए आवास' नाम का विस्तृत मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य सात साल में (2015-22) समूचे देश में चार करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ और शहरी इलाकों में 1.2 करोड़ आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाना है। यह कार्य तीन चरणों में किया जाएगा- प्रथम चरण अप्रेल 2015 से मार्च 2017, द्वितीय चरण अप्रेल 2017 से मार्च 2019 तथा तृतीय चरण अप्रेल 2019 से मार्च 2022 तक रहेगा। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' 2016 में शुरू की गई।

ऊर्जा:- भारत दुनिया का तीसरा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता देश है। विद्युत क्षेत्र में अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता करीब 334 गीगावॉट है, जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली 62 मेगावॉट ऊर्जा भी शामिल है। भारत ने 2017 में अपनी कुल आवश्यकता का करीब 82 प्रतिशत कच्चा तेल और 45 प्रतिशत प्राकृतिक गैस का आयात किया।

सड़क:- भारतमाला प्रथम चरण के लक्ष्य के तहत 2021-22 तक 2,000 किमी लम्बी तटवर्ती सड़कों और बंदगाहों को जोड़ने वाली सड़कों समेत 24,800 किमी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई वर्तमान 1.22 लाख किमी से बढ़ाकर 2022-23 तक 2 लाख किमी करने का लक्ष्य है। सिंगल/इंटरमीडिएट लेन वाले राजमार्गो को चौड़ा करना और 2022-23 तक इनकी कुल लम्बाई जो कि वर्तमान में कुल लम्बाई का 26.46 प्रतिशत है, को घटाकर 10 प्रतिशत के स्तर पर लाना है। सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या में 2020 तक 50 प्रतिशत की कमी लाना है।

रेलवे:- भारतीय रेलवे दुनिया में एकल प्रबंधन वाला तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रूट किमी. की दृष्टि से यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है (वर्ष 2017 में 67,368 किमी.) यह यात्री परिवहन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और माल ढुलाई में चौथा सबसे बड़ा संगठन है।

नागर विमानन:- विश्व आर्थिक मंच की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता रिपोर्ट-2018 में भारत हवाई परिवहन के बुनियादी ढांचे के लिहाज से दुनिया के 140 देशों में से 53वें स्थान पर रहा।

बंदरगाह और जहाजरानी:- भारत का समुद्र तट 7,500 किमी लम्बा है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। मात्रा की दृष्टि से भारत के विदेश व्यापार का 90 प्रतिशत और लागत की दृष्टि से 70 प्रतिशत बंदरगाहों से गुजरता है। भारत के तटों पर 12 प्रमुख बंदरगाह और 205 अन्य बंदरगाह हैं। जहाजरानी मंत्रालय का सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और विकास, बंदरगाहों के बीच सम्पर्क बढ़ाने, तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदायों की मदद करने और बंदरगाहों की अगुवाई में औद्योगीकरण पर जोर देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू और विदेशी व्यापार की लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाना है ताकि 2025 तक सालाना 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए की बचत हो सके। इसका एक अन्य उद्देश्य परिवहन के विभिन्न प्रकारों में जल परिवहन का हिस्सा बढ़ाकर दोगुना करना है।

■ समावेशी नीति से सबका विकास

सतत विकास का लक्ष्य जनवरी, 2016 में अमल में लाया और यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति और फंडिंग को 2030 तक निर्देशित करता रहेगा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और वह सभी तरह की असमानता को कम करने के लिए वैश्विक समाज एजेंडे को लेकर प्रतिबद्ध है। सतत विकास के 10वें लक्ष्य का मकसद सम्बन्धित देशों के भीतर असमानता को कम करना है। सतत विकास का लक्ष्य-16 सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, सभी को न्याय की उपलब्धता के लिए प्रावधान और सभी स्तरों पर प्रभावकारी और जवाबदेह संस्थान तैयार करना है।

देश के सभी जिलों में 1 फरवरी, 2017 से मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' है। इस योजना के तहत पहला बच्चा होने की स्थिति में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे 5,000 रुपए नकद मुहैया करना है।

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के सम्मान और स्वतंत्रता की सुरक्षा से जुड़े अहम उपाय माने जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत और अन्य अत्याचार से सम्बन्धित अपराधों के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया है। 103वें संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं।

■ अन्य प्रमुख तथ्य

- पिछले तीन साल में मनरेगा के तहत सालाना 235 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम के तहत पिछले चार साल में 1.69 लाख किमी. सड़कों का निर्माण कराया गया।
- आवास कार्यक्रम के तहत पिछले तीन साल में 10,949 ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया।

स्वच्छ देश-स्वस्थ समाज (नवम्बर)

■ ग्रामीण स्वच्छता रणनीति

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की शुरुआत की है। यह अभियान 2019 से 2029 तक 10 साल तक चलेगा। इसमें स्वच्छता संबंधी उन आदतों को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान के तहत लोगों में विकसित की गई।

■ रेलवे स्टेशनों की सफाई सर्वेक्षण रिपोर्ट-2019

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेल तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'स्टेशनों की सफाई सर्वेक्षण रिपोर्ट (गैर उपनगरीय और उपनगरीय स्टेशन) जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 720 स्टेशनों में राजस्थान के 7 स्टेशनों ने टॉप-10 में जगह बनाई, इनमें जयपुर, दुर्गापुरा, जोधपुर, सूरतगढ़, उदयपुर व अजमेर शामिल हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन को दिल्ली का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है।

■ स्वच्छता अर्थव्यवस्था व सफाईकर्मियों की गरिमा

स्वच्छता अर्थव्यवस्था का अर्थ केवल शौचालय बनाना नहीं है, बल्कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, कूड़े-कचरे का निपटान और उसे उपयोगी संसाधन में बदलना तथा संचालन में दक्षता के लिए डेटा को अनुकूलतम बनाने वाली डिजिटीकृत स्वच्छता प्रणाली, रख-रखाव, उपभोक्ता उपयोग और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं की अन्तर्दृष्टि भी शामिल है। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति अभियान और 2 अक्टूबर, 2019 में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने का अभियान शामिल है। वर्ष 2014-19 के बीच 699 जिलों की 2,58,657 ग्राम पंचायतों और 5,99,963 गांवों ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। शहरी इलाकों में इसी अवधि में 60 लाख घरेलू और 5.5 लाख सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया। हाथ से मैला साफ करने के लिए सफाईकर्मियों को काम पर रखने से रोकने के लिए सरकार ने हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी के रूप में नियोजन पर प्रतिबंध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 बनाया है जो 6 दिसम्बर, 2013 से लागू हुआ।

आयुष्मान भारत:- सितम्बर, 2018 से शुरू आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत 10.74 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग और दुर्बल परिवार (करीब 50 करोड़ आबादी) आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत हर परिवार को स्वास्थ्य सम्बन्धी हर प्रकार की देखभाल और अस्पताल में भर्ती के जरिए होने वाले इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाती है। एक साल में PMJAY ने 10,77,59,548 ई-कार्ड जारी किए हैं।

■ गांव-स्वच्छ भारत अभियान का मूल

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और इसके पुनर्गठित स्वरूप, समग्र स्वच्छता अभियान को क्रमशः 1986 और 1999 में लागू किया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार वर्ष 2005 में शुरू किया गया। 2012 में हर घर के लिए बड़ी वित्तीय प्रोत्साहन राशि (10,000 रुपए) के साथ निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया। 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई।

एसडीजे-6 का मकसद सबके लिए पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। सतत विकास लक्ष्य 6.2 के लक्ष्य के मुताबिक साल 2030 तक सबसे पर्याप्त और बराबर स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना, खुले में शौच के चलन को खत्म करना, महिलाओं, लड़कियों और अन्य वंचित पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

शहरीकरण (दिसम्बर)

■ करतारपुर साहिब कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवम्बर, 2019 को गुरदासपुर, पंजाब के करतारपुर साहिब कॉरिडोर में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया और तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। भारत ने जीरो प्वॉइंट, इंटरनेशनल बाउंड्री, डेरा बाबा नानक पर करतारपुर सहिब कॉरिडोर के संचालन के तौर तरीकों पर 24 अक्टूबर, 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमृतसर से डेरा बाबा नानक को जोड़ने वाले गुरदासपुर राजमार्ग पर 4.2 किलोमीटर लम्बी 4 लेन सड़क पर 120 करोड़ रुपए की लागत आई है।

■ शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण

संयुक्त राष्ट्र की 2018 की विश्व शहरीकरण संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 34 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है-यानी 2011 के बाद से लगभग तीन प्रतिशत अंकों की वृद्धि। 2031 तक यह और 6 प्रतिशत और 2051 तक आधे से अधिक देश की जनसंख्या शहरों में रह रही होगी। वर्तमान में शहर देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 65 प्रतिशत योगदान देते हैं, जिसके 2030 तक 70 प्रतिशत तक जाने की संभावना है। सतत् विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी 6.1 और विशेष रूप से 6.3) को हासिल करने के लिए देश में सुरक्षित पेयजल मुहैया करवाना और सेप्टेज सहित अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक शोधन की आवश्यकता है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत:- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख मिशनों में से एक अमृत का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून, 2015 को देश के 500 शहरों में किया गया। इसका उद्देश्य मूलभूत सेवाएं प्रदान कराना जैसे सभी घरों में जल की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत बनाना और गैर मोटर चालित परिवहन और सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पार्कों और हर शहर में कम से कम एक हरित स्थल उपलब्ध कराना है। केन्द्र प्रायोजित इस परियोजना का कुल परिव्यय 1,00,000 करोड़ रुपए है जिसमें 50,000 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहायता शामिल है जो वर्ष 2015-20 तक पांच वर्षों में दी जाएगी।

जल शक्ति अभियान (शहरी):- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2019 से जल संरक्षण, पुनर्स्थापना, पुनर्भरण और पुन: उपयोग पर अभियान चलाकर 'जल शक्ति अभियान' शुरू किया गया।

■ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

संसद द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की। नया अधिनियम बन जाने से पहले से लागू उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 निरस्त हो गया और उसका स्थान इस नए कानून ने ले लिया। इसमें उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में मध्यस्थता, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, पीड़ितों द्वारा सामूहिक रूप से मुकदमा दायर करने जैसे उपाय करने का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की कुछ विशेषताएं निम्न हैं-

1. उपभोक्ता की परिभाषा में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपभोक्ता आएंगे।
2. उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने, लागू करने और व्यापार के अनुचित तरीकों से उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जांच करने तथा जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने और उत्पाद वापस लेने, राशि लौटाने तथा वस्तु लौटाने को लागू करने तथा पीड़ित उपभोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से मुकदमा दायर करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है। अधिनियम के तहत जांच के उद्देश्य से महानिदेशक के नेतृत्व में केन्द्रीय प्राधिकरण के पास एक जांच शाखा होगी। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किसी निर्माता और पृष्ठांकनकर्ता पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग भी शामिल है। अगली बार ऐसे अपराध के लिए जुर्माना 50 लाख रुपए तक हो सकता है।
3. जिला आयोग के मामले में सहायक न्यायालय के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए, राज्य आयोग के मामले में 10 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय आयोग के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है।
4. किसी भी उत्पाद के कारण या उससे होने वाले नुकसान के लिए दावेदार के प्रति निर्माता की देयता निर्धारित कर 'उत्पाद देयता' कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
5. वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के तौर पर मध्यस्थता का प्रावधान भी किया गया है। अधिनियम की धारा 74 के अनुसार 'राज्य सरकार एक उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी।

6. उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश अनिवार्य होंगे, जिनमें धन वापसी अनुरोध को सम्पन्न करने के लिए 14 दिन की समय सीमा शामिल होगी।

■ दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण

'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज', जिसे 13 दिसम्बर, 2006 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयार्क में अंगीकर किया गया तथा विभिन्न राष्ट्रों के हस्ताक्षर के लिए मार्च, 2017 में सामने लाया गया। कन्वेंशन पर भारत समेत 82 देशों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए। 3 मई, 2008 से यह कन्वेंशन वैश्विक स्तर पर लागू हुआ और तब से इसे दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों के पैरोकार तथा उनके प्रति सकारात्मक रवैया जागृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाता है। यह कन्वेंशन दिव्यांगजनों को दया एवं करुणा के पात्र के रूप में न देखकर सक्षम मानवों के रूप में देखता है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 9, हस्ताक्षरकर्ता सरकारों पर सभी आवश्यक कदम उठाने का दायित्व डालता है ताकि दिव्यांगजनों की पहुंच अन्य लोगों के समान ही भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार और शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जनता को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं एवं सेवाओं तक सुनिश्चित की जा सके।

सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) के लिए वैश्विक स्तर पर एजेंडा 2030 अपनाया गया है, जिसमें 17 सस्टेनेबल गोल्स शामिल हैं। 'कोई न छूटे पीछे' के आदर्श पर आधारित यह नया एजेंडा एक समग्र दृष्टिकोण से हरेक के लिए सतत विकास पर जोर देता है। दिव्यांगता समावेशन का यह आदर्श विशेष रूप से एसडीजी संख्या 4, 8, 10 व 11 में झलकता है।

भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के द्वारा विकलांगता का प्रकार 07 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। 'सुगम्य भारत अभियान' दिव्यांगजनों को उनके विकास हेतु समान अवसर और पहुंच मुहैया कराने की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है। अभियान का लक्ष्य दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केन्द्रित है।

कुरूक्षेत्र

समृद्ध होते गांव (सितम्बर)

■ बदलते गांव, संवरता जीवन

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर प्रदान करती है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत देशभर में लगभग 11,00 प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं जो 330 व्यवसायों में आधुनिक कौशल प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों के द्वारा अब तक 2.70 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस योजना से मनरेगा को जोड़ा गया है, ताकि अकुशल श्रमिक कुशलता प्राप्त कर सकें। 'प्रोजेक्ट लाइफ' नामक इस अभिनव प्रयास के तहत कामगार परिवारों के युवाओं को निर्धारित और प्रमाणित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के अनुसार प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया जाता है।
- कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर स्वरोजगार के लिए 'स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम' शुरू किया गया है।
- 'एस्पायर' योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 80 आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर्स और 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 75,000 आकांक्षी उद्यमियों को कृषि व ग्रामीण औद्योगिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जाएगा।
- स्फूर्ति योजना को अधिक ऊर्जावान बनाया गया है। इसके लिए फिलहाल तीन व्यावसायिक क्षेत्र चुने गए हैं- बांस, शहद और खादी। योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 के दौरान 100 समूह विकसित किए जाएंगे और इनमें 50,000 कारीगरों को क्षमता विकास तथा बाजार सहायता प्रदान कर आर्थिक उद्धार की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान' (कुसुम) नाम से एक योजना चलाई जा रही है जिसमें एक ओर सिंचाई पंपों को डीजल/बिजली से चलाने की जगह सौर ऊर्जा से चलाने के लिए सहायता दी जा रही है तो दूसरी ओर खेतों में या बंजर भूमि में सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी और व्यवसायीकरण की राह आसन की गई है।

- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:- इस योजना के अंतर्गत देश के सभी योग्य गांवों और बस्तियों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। अब लक्ष्य यह है कि इस वर्ष गांव के हर घर में बिजली कनेक्शन हो। इसके लिए 'प्रधानमंत्री हर घर सहज बिजली योजना' (सौभाग्य) लागू की गई है, जिसमें गरीब परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है।
- जलशक्ति अभियान:- इस अभियान के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत में हर घर जल उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है।
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:- यह मिशन आज महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण उत्थान की अद्भुत मिसाल बन गया है। इसके अन्तर्गत गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है। उन्हें किसी एक कार्य के लिए कौशल प्रदान किया जाता है, जिसमें आमदनी की संभावना हो।
- श्यामा प्रसाद मुखजी रुर्बन मिशन:- गांवों में शहर जैसी सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के समूह यानी क्लसटर्स को आर्थिक रूप से सम्पन्न और सुविधाओं से युक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देशभर में कुल 300 क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य है। 'स्मार्ट गांव' बनाने के लिए प्रत्येक गांव में मुख्य रूप से तीन प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं- 1.व्यावसायिक कार्यकलापों द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, 2. कौशल विकास द्वारा स्थानीय स्तर पर उद्यमिता विकास, 3. उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास।

■ कृषि विकास व किसानों की समृद्धि हेतु पहल

हाल ही में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। भारत के पास दुनिया में 10वां सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि संसाधन है। भारत वैश्विक स्तर पर मसालों, दालों, दूध, चाय, काजू, आम, केला और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही गेहूं, चावल, फलों और सब्जियों, गन्ना, कपास और तिलहन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश 284.83 मिलियन टन के साथ खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। सरकार ने किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

■ ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान व तकनीक की पहल

अस्त्र:- 1970 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विज्ञान एवं तकनीकी अनुप्रयोग के अंग्रेजी में संक्षिप्ताक्षर 'अस्त्र' का प्रयोग किया गया। अस्त्र की अवधारणा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु के वैज्ञानिकों ने तैयार की। अस्त्र कार्यक्रम का मुख्य फोकस ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर केन्द्रित था। इसके अन्तर्गत ऊर्जा, किफायती मकान निर्माण तकनीक, पेयजल के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों की पहचान की गई।

स्टेम:- साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर फोकस रखते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना 'स्टेम' कार्यक्रम का मूलमंत्र हे। इस कार्यक्रम को 2014 के बाद प्रभावशाली तरीके से भारतीय परिवेश में क्रियान्वित किया गया।

तारा:- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सीड अनुभाग के अन्तर्गत 'तारा' (टेक्नोलॉजीकल एडवांसमेंट फार रूरल एरियाज) को संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीविकोपार्जन में सहायता और सामाजिक लाभ के लिए ऐसे गैर सरकारी संगठनों को सहायता पहुंचाना है जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसमें नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुकूलन पर बल दिया जाता है।

सीड:- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सीड (साइंस फार इक्विटी एम्पॉवरमेंट एंड डेवलपमेंट) योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर तकनीकी सशक्तीकरण तथा सतत् जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अन्तर्गत अभिप्रेरित वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को समाज के वंचित व गरीब समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त विज्ञान वतकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाता है।

टीआईटीई:- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की टीआईटीई (टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर ट्राइबल एम्पॉवरमेंट) उप योजना का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के दीर्घकालिक अनुप्रयोग के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जीवन दशा में सुधार लाकर उन्हें सशक्त बनाना है।

■ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में असीमित विकास

नवीकरणीय ऊर्जा की संचयी स्थापित क्षमता 31 मार्च, 2019 तक 78 गीगावॉट हो गई है। 30 जून, 2019 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पास 80.47 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल हो चुकी है, जिसमें में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी क्रमशः 29.55 व 36.37 गीगावॉट है। बायोमास और छोटी पनबिजली इकाइयों की हिस्सेदारी क्रमशः 9.81 गीगावॉट और 4.6 गीगावॉट है।

केन्द्र सरकार द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) की शुरुआत की गई है। किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा महैया कराने के उद्देश्य से इस अभियान का आरम्भ किया गया है। कुसुम योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल या बिजली के पम्प को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। इस योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए तो करेंगे ही, साथ ही बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकेंगे। इस योजना के तीन घटक है, जिनका लक्ष्य 2022 तक 25.750 मेगावॉट की सौर क्षमता को बढ़ाना है।

भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अन्तरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस संगठन में 121 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जो मकर और कर्क रेखा पर पड़ते हैं। इस गठबंधन ने 6 दिसम्बर, 2017 को भारत में अपने मुख्यालय के साथ कानूनी इकाई के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। 11 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में अन्तरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थापन सम्मेलन आयेजित किया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में गोबर धन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें कृषि व पशु अपशिष्ट पदार्थ को कम्पोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा।

■ बाल स्वास्थ्य और पोषाहार योजनाएं

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत ने देश में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर में कमी करके 2030 तक इसे जीवित जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों पर 25 करने की वचनबद्धता व्यक्त की है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिदृश्य में इस संख्या को 2025 तक 23 पर लाने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय पोषण अभियानः- वर्ष 2017-18 में शुरू किए गए पोषण अभियान में देश में सबसे पिछड़े जिलों में अल्प पोषण, शारीरिक बढ़वार रुकने, रक्ताल्पता और जन्म के समय कम वजन के मामलों में कमी लाने का लक्ष्य निधरित किया गया है। इसमें 2019-20 तक देश के सभी राज्यों और जिलों को अभियान के दायरे में लाने का भी लक्ष्य रखा है जिनमें से 315 को 2017-18 में, 235 को 2018-19 में और बाकी सभी जिलों को 2019-20 तक अभियान के दायरे में लाने का लक्ष्य है।

समन्वित बाल विकास सेवा :- 2 अक्टूबर, 1975 में शुरू समन्वित बाल विकास सेवा सबसे बड़ा पोषण प्रतिपूर्ति कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 0 से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना है।

■ जल संरक्षण की दिशा में पहल

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने 1 जुलाई, 2019 को जल संरक्षण महाभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश में 256 जिलों के ज्यादा प्रभावित 1592 ब्लॉकों को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया। इस अभियान को दो चरणों में चलाना तय किया गया। पहला चरण 1 जुलाई, 2019 से शुरू होकर 15 सितम्बर, 2019 तक चलेगा तो दूसरा चरण 1 अक्टूबर, 2019 से शुरू होकर 30 नवम्बर, 2019 तक चलेगा। इस अभियान का फोकस पानी के कम दबाव वाले जिलों और ब्लॉकों पर होगा। इस अभियान का मकसद जल संरक्षण के फायदों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है ताकि देश के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने में सहभागिता और जागरूकता का लाभ मिल सके। जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के हर घर में पीने का साथ पानी मुहैया करना है।

साल 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 60 करोड़ लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश के करीब 75 फीसदी घरों में आज भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, देश में 70 फीसदी पानी दूषित है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत दुनिया की 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। भूजल के इस्तेमाल करने के मामले में भारत दुनिया में पहले नम्बर पर है।

■ स्वच्छ पर्यावरण और सफाई हेतु पहल

भारत में ग्रामीण क्षेत्र वह है 'जिसमें लोगों की आबादी 5,000 व जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो तथा कृषि पर आश्रित कामकाजी लोगों की संख्या कम से कम 25 प्रतिशत हो'।

स्वच्छ भारत मिशनः- 2 अक्टूबर, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देशभर में शुरू किया गया। दो उपमिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) इसके अन्तर्गत आते हैं। दोनों मिशनों का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर सही रूप में श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 48ए के 42वें संशोधन के अनुसार 'राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश में वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।'

कृषि क्षेत्र में सुधार (अक्टूबर)

■ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सुधार

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः- 'हर खेत को पानी' लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मकसद सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में हर तरह की मदद उपलब्ध कराना है। मसलन जल संसाधन, वितरण नेटवर्क और खेत के स्तर पर उपयोग। इस योजना में लघु सिंचाई पहलू के तहत 12 लाख हेक्टेयर सालाना की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः- भारत सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों के मदद के लिए वर्ष 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना में सभी किसानों को शामिल करते हुए जमीन सम्बन्धी शर्त (2 हेक्टेयर व इससे कम जमीन का प्रावधान) हटा दी है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनाः- इसके तहत योजना से जुड़ी शर्तों को पूरा करने वाले छोटे व सीमान्त किसानों की उम्र 60 साल होने पर उन्हें न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। यह स्वैच्छिक और योगदान करने वाली पेंशन योजना है और इसमें योगदान के लिए आयु 18 से 40 वर्ष है। इसमें अपनी उम्र के हिसाब से 55 से 200 रुपए तक का योगदान कर सकते हैं। इस पेंशन योजना में केन्द्र सरकार इतनी ही राशि अपनी तरफ से पेंशन फंड में देगी। इसके लिए 9 अगस्त, 2019 से पंजीकरण शुरू हो गया है।

बाजार हस्तक्षेप योजनाः- जल्दी खराब होने वाली और पीएसएस के दायरे से बाहर फल, सब्जियों व अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गई है।

राष्ट्रीय बांस मिशनः- बांस क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला आधारित सम्पूर्ण विकास के मकसद से केन्द्रीय बजट 2018-19 में 'राष्ट्रीय बांस मिशन' की शुरुआत की गई।

राष्ट्रीय गोकुल मिशनः- गायों और भैंसों की देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए दिसम्बर, 2014 में 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' की शुरुआत की गई।

राष्ट्रीय पशुधन मिशनः- पशुधन, खासतौर पर छोटे पशुओं के विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ 2014-15 में 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' की शुरुआत की गई।

■ कृषि संबंधी सुधारों के लिए रोडमैप

उर्वरक क्षेत्र में सुधारः- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की हर खेतिहर परिवार में 100 प्रतिशत पहुंच है। 216 मिलियन से अधिक मृदा कार्ड वितरित किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधनः- जनवरी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया। इसमें अपने पूर्ववर्ती बीमा योजनाओं का विलय किया गया।

आवश्यकता अनुरूप ऋणः- सारंगी समिति (2016) की सस्ते कर्ज पर सिफारिशें सरकार द्वारा लागू की गई हैं। तीन लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसली ऋण पर सस्ती ब्याज दर और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आधार को व्यापक बनाया गया है जिसमें सावधि ऋण और उपभोग की जरूरतों के अलावा आकस्मिक मृत्यु पर जोखिम कवर भी शामिल है।

■ खेती की बेहतरीन तकनीकें

संरक्षण खेतीः- संरक्षण खेती की परिभाषा ऐसी टिकाऊ कृषि उत्पादन प्रणाली के रूप में की जाती है जिसमें खेती के ऐसे सुनिश्चित तौर-तरीके अपनाए जाते हैं जो फसलों और प्रत्येक क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होते हैं

ताकि मृदा प्रबंधन तकनीकों से मिट्टी के क्षरण और जमीन के बंजर होने की रोकथाम की जा सके। इसकी गुणवत्ता सुधारी जा सके और जैव विविधता को भी बेहतर बनाया जा सके।

समन्वित खेती:- सीमान्त और छोटे किसान अगर खेती के साथ पशुपालन को भी समन्वित कर लें तो इससे सिर्फ फसल उगाने के मुकाबले अधिक अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

सुनिश्चित पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड:- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी, 2015 में शुरू की गई थी।

जैविक खेती:- जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहाल करने में मदद मिलती है। इससे पर्यावरण का संरक्षण होता है, जैव विविधता बढ़ती है, फसलों की उत्पादकता बनी रहती है और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है।

समन्वित फसल प्रबंधन:- समन्वित फसल प्रबंधन का अर्थ है खेती के बेहतर तौर-तरीकों जैसे समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, समन्वित खरपतवार प्रबंधन, समन्वित बीमारी प्रबंधन और समन्वित कीट प्रबंधन आदि का उपयोग करके अच्छी फसल लेना। इस तरह आईसीएम, फसलों के उत्पादन की एक ऐसी वैकल्पिक प्रणाली है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है और उनमें वृद्धि करती है तथा आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक और चिरस्थायी आधार पर गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है।

संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य फसलों के लगातार विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि जलवायु संबंधी प्रतिकूल स्थितियों में भी अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जा सके।

■ ई-नाम

देश में एक वर्ष में बर्बाद हुए खाद्यान्न का मूल्य करीब 92 हजार करोड़ रुपए है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल है जो मौजूदा भौतिक रूप से विनियमित थोक बाजार को एक आभासी मंच के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रेल, 2016 को इसकी विधिवत शुरुआत की थी। सरकार का मार्च, 2018 तक देश की 585 मंडियों को ई-नाम में शामिल करने का लक्ष्य था, जिसे प्राप्त कर लिया गया है। 25 जिंसों के साथ शुरू किए गए इस पोर्टल पर अब 150 जिंसों के ई व्यापार की सुविधा उपलब्ध है।

■ महिला किसानों के सशक्तीकरण हेतु पहल

एक अध्ययन के मुताबिक ग्रामीण भारत में 84 प्रतिशत महिलाओं की आजीविका कृषि पर आधारित है। अपने खेतों में जुताई करने वाले किसानों में 33 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि खेतिहर मजदूरों में इनका प्रतिशत 47 है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना:- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं के हालात सुधारने और उपलब्ध अवसरों का लाभ उन तक पहुंचाते हुए उन्हें सशक्त करना है। इसे दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रखा गया है।

■ बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली

केन्द्र सरकार की ओर से 2014-15 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का लक्ष्य हर किसान का खेत सींचने के साथ 'प्रति बूंद अधिक फसल' पैदा करने की व्यवस्था करना है। भारत की स्थिति पर गौर करें तो कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें खेती करीब 144 मिलियन हेक्टेयर पर होती है, जबकि लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर है।

■ आय बढ़ाने में सहायक कृषि सम्बद्ध क्षेत्र

डेयरी और पशुपालन:- भारत विश्व में शीर्ष दुग्ध उत्पादक के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है और लगभग 17 करोड़ टन दूध उत्पादन के साथ वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग 19 प्रतिशत योगदान करता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की घोषणा की। इस योजना पर 750 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

गोबर धन योजना:- पिछले वर्ष के बजट में गोबरधन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य गोबर, घरेलू कचरे तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों से बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत गांवों के मवेशियों का गोबर एकत्र करना और उसे जैविक खाद, बायोगैस अथवा बायो सीएनजी बनाने वाले उद्यमियों को बेचना शामिल है।

स्फूर्ति योजनाः- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 'स्फूर्ति' (स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) योजना संचालित की जा रही है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के परम्परागत उद्यमों और हुनरमंद कर्मियों को संगठित कर दीर्घावधि रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने हुए मजबूत करना, रोजगार के टिकाऊ अवसरों का सृजन करना, तैयार उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था, हुनर उन्नयन आदि की सुविधा प्रदान करना है।

ग्रामीण शिक्षा (नवम्बर)

■ ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा : नीति और नियोजन

2011 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर 68 प्रतिशत के आस-पास थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 84 प्रतिशत थी। इतना ही नहीं, केवल 59 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के साक्षर होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि 2011 में शहरी इलाकों में 80 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं।

समग्र शिक्षाः- केन्द्र द्वारा पहले से प्रायोजित तीन योजनाओं-सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना का विलय किया गया है और स्कूल पूर्व कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के विकास के लिए हाल ही में समन्वित योजना के तौर पर शुरू किया गया है।

पुनर्गठित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयः- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत पुनर्गठित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत अब शैक्षिक दुष्टि से पिछड़े ऐसे हर ब्लॉक में, जहां किसी भी योजना के तहत कोई आवासीय विद्यालय नहीं है, बालिकाओं के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षित बालिकाओं के लिए 3700 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होस्टलों का विस्तार कर उनमें 12वीं तक की कक्षाओं की बालिकाओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी।

पुनर्गठित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजनाः- जनजातीय कार्य मंत्रालय की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नाम की इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को, खासतौर पर दूर-दराज इलाकों के विद्यार्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुफ्त प्रदान करना है। वर्ष 2022 तक ऐसे प्रत्येक बलॉक में, जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है और जहां कम से कम 20,000 जनजातीय आबादी है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोला जाएगा।

स्वच्छ विद्यालय पहल :- 15 अगस्त, 2014 को भारत को साफ-सुथरा बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के जवाब में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग शौचालय के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए स्वच्छ विद्यालय पहल का शुभारंभ किया। यह अभियान एक साल के भीतर 2015 में पूरा हुआ।

डिजिटल पहलः- हाल में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किए जाने का उद्देश्य देशभर में सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में डिजिटल बोर्ड की शुरुआत करना है। इसी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले चरण में 300 विश्वविद्यालयों और 10,000 कॉलेजों को डिजिटल बोर्ड के दायरे में लाने की योजना बनाई है।

निष्ठा कार्यक्रमः- हाल ही में नेशनल इनीशिएटिव फार स्कूल हैड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी स्कूल प्रमुखों और अध्यापकों के समग्र उन्नयन के लिए राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल स्तर के 42 लाख अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयकों और क्लस्टर संसाधन केन्द्र समन्वयकों की क्षमता सृजित करना है।

उन्नत भारत अभियान और स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिपः- उन्नत भारत अभियान के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्था को कम से कम पांच गांवों से जोड़ा जाएगा, ताकि उनके विद्यार्थी तथा शैक्षणिक संकाय के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविकताओं को समझने के कार्य से जुड़ें और गांवों के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अभिनव तौर-तरीकों और टेक्नोलॉजी की पहचान करें। स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप का उद्देश्य कॉलेजों के नौजवानों को स्वच्छता के कार्य से जोड़ना है।

■ ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने की रणनीति

सर्व शिक्षा अभियान 2000 में शुरू किया गया। मध्याह्न भोजन योजना 2001 में लागू हुई और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ।

प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किए गए 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम' यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे बड़े पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव लाना है।

नीति आयोग ने स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। इसमें राज्यों को उनकी स्कूल शिक्षा प्रणाली की सफलता के आधार पर पहली बार वर्गीकृत किया गया है।

■ ग्रामीण भारत में बेहतर स्कूली शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968,1986) के अनुसार शिक्षकों के स्तर और शिक्षण-प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया जाए और उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983-85) के अनुसार शिक्षकों की प्रतिष्ठा, कार्यदशा सुधारने एवं कल्याण हेतु शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षकों को संग्रहीत राष्ट्रीय वेतनमान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती को संस्था आधारित करते हुए स्थानांतरण की वर्तमान प्रणाली से बाहर निकलने की जरूरत है। यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) 'शिक्षा बिना बोझ के' में लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005-08) के अनुसार एक व्यवसाय के रूप में स्कूली शिक्षकों की प्रतिष्ठा बहाल किए जाने और योग्य तथा प्रतिबद्ध अध्यापकों को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के अनुसार बच्चा, सीखते हुए ज्ञान का सृजन करता है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षायी अनुभव आयोजित करें, ताकि सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिल पाए। वर्मा कमीशन (2012) में शिक्षकों व अध्यापकों-शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक पूरी शिखा पर एक समग्र शिक्षा प्रयोजना को वर्ष 2018 में लागू किया।

■ बड़े बदलाव का सूत्रधार शिक्षा का अधिकार

साल 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21ए को शामिल किया गया। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को कानून के मुताबिक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रेल, 2010 से लागू हुआ। यह कानून देश में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है और सभी प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक न्यूनतम शर्तों के पालन की भी बात करता है। कानून के मुताबिक, सभी निजी स्कूलों को निर्धन समुदाय के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करना जरूरी है। इन सीटों से जुड़ी फीस का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। साथ ही इन सीटों के लिए चंदा या किसी प्रकार का अन्य शुल्क लेने पर मनाही है और दाखिले के लिए किसी बच्चे या माता-पिता को इंटरव्यू भी नहीं देना होगा।

■ ध्रुव

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 10 अक्टूबर, 2019 को बेंगलूरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया। ध्रुव कार्यक्रम देश में प्रतिभाशाली छात्रों की तलाश के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा और ऐसे छात्रों को विज्ञान, ललित कला और रचनात्मक लेखन आदि जैसे उनकी रुचि के विषयों में उत्कृष्टता हासिल करने में मददगार होगा।

■ समावेशी विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा

टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का प्रारूप पेश किया गया। इस नीति में संचार माध्यमों के उपयोग पर जोर दिया गया। अब इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2019 में पुनः शिक्षा नीति का प्रारूप पेश किया गया है।

■ ग्रामीण शिक्षा और कौशल विकास

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाः- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (1.0) वर्ष 2015-16 में युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देकर बेहतर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद यह योजना (2.0) वृहद रूप से दूसरी बार 2016-20 के मध्य एक करोड़ युवाओं को निःशुल्क 2 से 6 माह तक के प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल बनाने की दिशा में बेहतर प्रयास है। वर्ष 2018 के बाद से एक नई पहल के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2.0) के तहत प्रमाणित प्रत्येक उम्मीदवार को 2 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि के तहत कवर किया जाता है जो दो साल तक वैध है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनाः- 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को समर्पित यह योजना सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया अभियानों से सम्बन्धित है। यह योजना देश के 669 जिलों के युवाओं को प्रभावित करती है। ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी दूर करना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कौशलों का विकास करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।

■ सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की अधिसूचना 20 सितम्बर, 2019 को जारी की। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत एवं अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित करना है। इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर की गई। पुरस्कार में एक पदक व प्रशस्ति पत्र होगा। एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह अति असाधारण और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।

■ प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 24 सितम्बर, 2019 को 'ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान स्वच्छ भारत अभियान को जनांदोलन में परिवर्तित करने वाले और इसे अपने दैनिक जीवन का अंग बनाने वाले भारतीयों को समर्पित किया।

■ अन्य प्रमुख तथ्य

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2019 को अमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस 2019 की शुरुआत की। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें याद में डाक टिकट व चांदी का सिक्का जारी किया।

कृषि आधारित उद्योग (दिसम्बर)

■ भारत में कृषि आधारित उद्योगों का अवलोकन

भारत में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि, 20 कृषि जलवायु क्षेत्र और 15 प्रमुख जलवायु हैं। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2001 में देश में कुल कृषकों की संख्या 12.73 करोड़ से घटकर 11.88 करोड़ रह गई है। कृषि का जीडीपी में करीब 18 प्रतिशत योगदान है।

चुनिंदा सरकारी पहलः-

1. खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थः- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKYS) के तहत अपनी योजनाओं को 2016-20 की अवधि के लिए रुपए 6,000 करोड़ के आवंटन के साथ पुनः संरचित किया है। योजना में निम्न घटक स्थापित किए गए हैं- मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यविर्धित आधारभूत ढांचा, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन आधारभूत ढांचा, मानव संसाधन विकास तथा संरचनाएं। PMKYS में तीन नई योजनाएं शामिल हैं- कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए आधारभूत संरचना, विनिर्माण और विपणन सुविधाओं का निर्माण तथा खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण इकाइयों की स्थापना में सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ मजबूत आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार।

2. कपड़ा उद्योगः- कपड़ा उद्योग 4.5 करोड़ लोगों को सीधे और अन्य 6 करोड़ लोगों को सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है।

3. जूट उद्योगः- भारत में जूट उद्योग की स्थापित क्षमता 16.5 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 11.5 लाख मीट्रिक टन जूट का उत्पादन होता है।

■ कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमः- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEJP) की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की मदद से स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से कृषि उद्योगों के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जा रही है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनाः- हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कृषि-समुद्री उत्पादों एवं कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण

को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2016 में वर्ष 2020 की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

नाबार्ड :- ऋण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई है। यह संस्थान कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत वर्ष 1998 में भारतीय बैंकों द्वारा की गई थी।

नाफेड:- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन मंच (नाफेड) भारत की बहु-राज्य सहकारी सोसायटीज अधि नियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को की गई थी।

■ मिशन इन्द्रधनुष 2.0

वर्ष 1978 में भारत सरकार ने 'विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम' शुरू किया, जिसे बाद में वर्ष 1985 में यूनिवर्सल यानी सर्वजनीन टीकाकरण कार्यक्रम नाम दिया गया। इसका उद्देश्य बच्चों में रोकथाम की जा सकने वाली बीमारियों के टीके लगाकर रुग्णता और मृत्यु से बचाव करना था। बचपन में टीकाकरण का दायरा सीमित होने के वजह से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2014 में 'मिशन इन्द्रधनुष' शुरू किया, जिसका उद्देश्य नाजुक, सुविधाओं की कमी वाले, प्रतिरोध करने वाले और दुर्गम क्षेत्रों की आबादी तक पहुंच बनाना था। इसके तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण अभियान में शामिल करना था जो इससे छूट गए थे।

अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'सघन मिशन इन्द्रधनुष' का शुभारम्भ किया। इसका उद्देश्य लगातार टीकाकरण के निम्न स्तर वाले जिलों तथा शहरी इलाकों में पूर्ण टीकाकरण की दिशा में 90 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना था। सघन मिशन इन्द्रधनुष से भारत के 190 चुने हुए जिलों में पूरी तरह से टीकाकृत बच्चों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।

सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 के शुभारम्भ से भारत के सामने पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में और कमी लाकर वर्ष 2030 तक रोकथाम की जा सकने वाली मौतों से बचाकर चिर स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर है।

■ आर्थिक विकास में सहायक कपड़ा उद्योग

औद्योगिक उत्पादन में कपड़ा और वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। साथ ही कुल निर्यात से होने वाली कुल आय में इस उद्योग की हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत, जबकि जीडीपी में योगदान 2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय घरेलू सर्वे 2017 के अनुमानों के मुताबिक इस उद्योग का बाजार 163. 70 अबर डॉलर का है।

■ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावे की योजनाएं

विश्व में दूध, केला, आम, मसाले, झींगा मछली और दालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इसके अलावा अनाजों, सब्जियों और चाय के उत्पादन में भारत दूसरे नम्बर पर है। हमारे देश में फल और सब्जियों के प्रसंस्करण का वर्तमान स्तर 2 प्रतिशत, पोल्ट्री उत्पादों का 6 प्रतिशत, समुद्री उत्पादों का 8 प्रतिशत और दूध का 35 प्रतिशत है यद्यपि विभिन्न कारणों से 30 से 35 प्रतिशत कृषि उत्पाद हर वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। राष्ट्रीय आय में 14.8 प्रतिशत के योगदान के साथ-साथ कृषि देश की 65 प्रतिशत आबादी को रोजगार व आजीविका भी प्रदान करती है।

सरकारी योजनाएं:-

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:- भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े-लिखे हैं या जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। साथ ही, देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ा प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यतानुसार रोजगार के काबिल बनाना है। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40.2 करोड़ युवाओं को शामिल करने की योजना है।

2. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना:- कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के लिए भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग के चक्र 2016-20 की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए किया है। इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केन्द्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है।

3. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम:- भारत सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप

ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अन्तर्गत देश के हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा कृषि आधारित उद्योग-धंधों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

4. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना :- ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया है। इस योजना का लाभ 5.5 करोड़ कुशल युवाओं को मिलने की उम्मीद है। यह योजना मेक इन इंडिया की मुख्य भागीदार है। समाज के वंचित समुदायों के साथ-साथ दिव्यांगजन और महिलाओं को भी कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण देकर उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आज देश में 1100 से ज्यादा प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहे हैं जो लगभग 300 व्यवसायों में आधुनिक कौशल प्रदान करते हैं।

5. एक्सपायर:- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में इनोवेशन, ऑन्त्रप्रन्योरशिप (स्वरोजगार) और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे हाल में नए प्रावधानों के साथ अधिक उपयोगी बनाया गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से दौरान 80 आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर्स और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

■ अन्य प्रमुख तथ्य

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2018 में भारत की खाद्य प्रसंस्करण नीति पेश की। सरकार ने भारत को दुनिया का खाद्य कारखाना और वैश्विक खाद्य बाजार बनाने पर जोर दिया है।
- देश के 14.7 करोड़ परिवारों में से 7.1 करोड़ से अधिक परिवार अपनी आजीविका के लिए डेयरी क्षेत्र पर निर्भर हैं।